● वर्ष-3
● अंक-51
रायपुर, शनिवार
07 अक्टूबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› रुके हुए और बिगड़े हुए काम ...

लोकतंत्र की नींव पंचायत और नगर पालिकाओं में बसती है : प्रियंका

कांकेर में पंचायती राज महासम्मेलन में कहा- छत्तीसगढ़ में जितने भी कार्य हो रहे हैं स्थानीय निकाय से हो रहे हैं

कांकेर। नगरीय निकाय व पंचायती राज महासम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की नींव पंचायत में, गांव में, नगर पालिकाओं में बसती है। आज आपके प्रदेश की चर्चा पूरे देश में है कितना काम कितना तेजी से विकास हो रहा है। यह विकास गांव में हो रहा है यहां का किसान खुश हैऔर जितने भी कार्य हो रहे हैं स्थानीय निकाय से हो रहे हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पेसा कानून लागू कर इसे और भी सशक्त बनाया है।

एक समय था जब जनप्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी उससे यह होता था कि जितने निर्णय लेने थे वह सभी एक जगह केंद्रित हो जाते थे। कई ऐसे कार्य होते थे जिन्हें होने में बहुत समय लगता था या कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत ही नहीं थी लेकिन इन सब में बहुत समय लगता था। दिल्ली जाना पड़ता था, रायपुर आना पड़ता था तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाया जाए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, इसका निर्णय गांव करें, गांव के ही प्रतिनिधि करें।

आप सब यहां बैठे हैं, आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत में किस तरह के काम होने हैं और किस तरह के कामों को होना चाहिए।आप अपने लोगों के हित में निर्णय ले सके, यही मूल बात है।लोकतंत्र की नींव पंचायत में, गांव में, नगर पालिकाओं में बसती है।

इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी, शायद आपने वो फ़ोटो देखी होगी जिसमें वह बस्तर की महिलाओं के साथ नाच रही थी। बस्तर से मेरा बहुत पुराना नाता है। इंदिरा जी ने उस समय जो कहा था, भूपेश बघेल आज उसे पूरा कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से आज प्रदेशभर में विद्यालय, महाविद्यालय खोले गए हैं। आज बस्तर एक अंतरराष्ट्रीय नाम बन गया है। मॉडल बन गया है। छत्तीसगढ़ में आज देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है। आज आपकी सरकार आपको आगे बढाने का काम कर रही है, यहां का मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है।

बस्तर आज प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, बहुत लोगो को रोजगार मिल रहा

है। 60 से ज्यादा वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। इतना सारा काम आपके क्षेत्र में हो रहा है, लोग पहले यहां आने से डरते थे, हर तरफ हिंसा भय और उत्पीडन् था, आज सरकार ने इस रास्ते से आपको निकाला है। जनता की भलाई के लिए नियत की जरूरत है। इंदिरा जी की नीयत सही थी इसलिए आज भी उन पर भरोसा है। बघेल जी पर भी भरोसा है क्योंकि उन्होंने सभी वर्ग के लिए काम किये हैं। मनरेगा योजना भी हमारी सरकार ने लायी है।

प्रियंका ने कहा कि भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ में हिंसा का राज था। जिसे कांग्रेस ने पांच साल में निकाला। पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ की चर्चा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद रहे। 502 कार्यों के 800 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कांकेर में प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने किया। इसके बाद प्रियंका गांधी अलग अलग स्टॉल्स पहुंची और उनका निरीक्षण किया। प्रियंका गांधी ने स्कूली बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। स्कूली बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। प्रियंका गांधी ने चरखा चलाया और सूत भी काता। मंच पर पहुंचने के बाद गौर सिंग पहनाकर प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया। कांकेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी फूलों की माला से प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया।

पंचायती राज सम्मेलन में कवासी लखमा ने कहा कि प्रियंका गांधी कांकेर में आई हैं। उनका बहुत स्वागत है। पंचायती राज के तहत गांवों के विकास की शुरुआत राजीव गांधी ने किया। लखमा ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने पिछले 15 साल में प्रदेश के आदिवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया। मोदी ने कहा कि 15 लाख रुपये देंगे। लेकिन क्या वो मिला। लखमा ने बस्तर की 12 सीटें जिताने का आह्वान प्रदेशवासियों से किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि देश में पंचायती राज का अधिकार राजीव गांधी ने किया। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पेसा कानून लागू हुआ। बस्तर का विकास सिर्फ कांग्रेस ने ही किया।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बस्तर से गांधी परिवार का हमेशा से लगाव रहा है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद बस्तर का विकास हुआ है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों को सड़क, बिजली, पानी, न्याय, शिक्षा सभी से वंचित रखा। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद बस्तर का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। 57 विधानसभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं होता है।

पोस्टर पर भड़कीं प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस ग्राफिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है जिसमें उनके भाई और पार्टी नेता राहुल गांधी को दाढ़ी वाले चेहरे और रावण की याद दिलाने वाले सात सिर के साथ दिखाया गया है। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स पोस्ट के जरीए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किये जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज़्यादा समय नहीं बीता, आपने शुचिता की क़सम खायी थी। क्या वादों की तरह क़समें भी भूल गये?भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पौराणिक चरित्र रावण के रूप में चित्रित करने वाला एक ग्राफिक साझा करके उन पर तीखा हमला बोला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल द्वारा साझा किए गए पोस्टर की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया गया कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने कट्टर आलोचक को खत्म करने की साजिश रच रही है। पोस्टर में गांधी की एक विकृत छवि है जिसमें उन्हें पौराणिक राक्षस राजा रावण के रूप में चित्रित किया गया है। पोस्टर के कैप्शन में उन्हें दुष्ट, धर्म-विरोधी, राम-विरोधी बताया गया।

72 साल में भारत का सबसे सफल एशियाड

हांगझोऊ। हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया है। %इस बार 100 पार% का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय दल ने 100 से ज्यादा पदक पक्के कर लिए हैं। भारत के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आजादी के 75वें वर्ष के अमृतकाल में देश 19वें एशियाई खेलों में पदकों का शतक पूरा करने जा रहा है। स्पर्धाओं के 13वें दिन भारत ने हॉकी के स्वर्ण सहित नौ पदक जीतकर पदकों की संख्या 95 तक पहुंचा दी है। सौ पदकों का पार होना इसलिए तय है क्योंकि कई स्पर्धाओं में हम फाइनल में हैं, बस मेडल का रंग तय होना है। एशियाई खेलों के आखिरी दिन यानी शनिवार को सात अन्य पदक आने हैं और पदकों का आंकड़ा 100 पार हो जाएगा।

शुक्रवार को कुश्ती में तीन कांस्य पदक मिले। तीरंदाजी में एक रजत, एक कांस्य, ब्रिज में रजत, बैडमिंटन में एक कांस्य के अलावा सेपकटेकरॉ में मिला पदक तो ऐतिहासिक है। हॉकी के स्वर्ण पदक की सर्वाधिक खुशी है क्योंकि इसके साथ अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट भी पक्का हो गया है।

सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक

यह एशियाई खेलों के

फाइनल में जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पर कब्जा किया। भारत ने कुल 68 गोल दागे।

इतिहास में भी पहली बार है जब भारत ने 20 से अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा स्वर्ण 72 साल पहले यानी 1951 दिल्ली एशियाई खेलों में आए थे। तब भारत ने 15 स्वर्ण जीते थे। भारत ने जकार्ता में हुए पिछले एशियाई खेलों के 70 पदकों के कीर्तिमान को तो पहले ही ध्वस्त कर दिया था और अब तो 100 पदकों का संकल्प लेकर चीन जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने अपने लक्ष्य को भी सिद्ध भी कर लिया है। इस साल निशानेबाजी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया।

अभी ये सात पदक तय

- कबड्डी में दो पदक = भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं
- तीरंदाजी में तीन पदक = कंपाउंड एकल फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी, महिला एकल फाइनल में ज्योति सुरेखा
- क्रिकेट में एक पदक= भारत ने बांग्लादेश को नौ विकेट से हराकर क्रिकेट के फाइनल में कर लिया है प्रवेश
- बैडमिंटन में एक पदक= बैडमिंटन पुरुष युगल में सात्विक-चिराग की जोड़ी फाइनल में पहुंची।

विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत केतका में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के निर्देषन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम, संयुक्त कलेक्टर एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रियंका वर्मा के मार्गदर्षन में स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केतका के छात्र-छात्राओं धारा ई.व्ही.एम., व्ही.व्ही. पैट, स्वीप एवं स्वास्तिक आदि आकृतियां प्रदर्शित की गई।

प्रमुख समाचार

दो वर्ष में पूरी तरह खत्म हो जाएगा वामपंथी उग्रवाद: शाह

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जहां 2010 की तुलना में 2022 में हिंसक घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी शामिल हुए, वहीं ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राज्य के मंत्रियों ने किया। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इसे इसके सभी रूपों में उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि दो वर्ष में देश से वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। पिछले पांच वर्षों में देश में वामपंथी उग्रवाद सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने 2015 में एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने कहा कि नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है।

मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में गुरुवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई कड़े सवाल किए। लंबी दलीलों के बाद मामले की सुनवाई 12 अक्तूबर तक टाल दी गई। दरअसल, मनीष सिसोदिया ने दो याचिकाएं दाखिल की है, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को चुनौती दी गई है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अभी क्या हुआ है? आप नेता का पक्ष किसने रखा तो सरकार की तरफ से कौन पेश हुआ? कोर्ट ने एजेसंसियों को लेकर क्या कहा? अगली सुनवाई कब होनी है? सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने की। पीठ सिसोदिया द्वारा दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले सिसोदिया को सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही जांच के संबंध में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

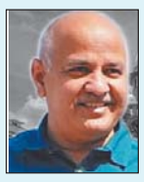

एनसीपी विवाद पर अब 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। एनसीपी का असली बॉस कौन। यह लड़ाई फिलहाल चुनाव आयोग के समक्ष है। आज चुनाव आयोग के समक्ष शरद पवार गुट ने अपना पक्ष रखा है। जानकारी के मुताबिक अजित पवार गुट अब सोमवार को अपना पक्ष रखेगा। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब सोमवार को इस मामले को लेकर अगले सुनवाई होगी। इस दौरान चुनाव आयोग के समक्ष शरद पवार खुद पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अजित पवार का दवा काल्पनिक है। आपको बता दें की एनसीपी फिलहाल दो गुटों में बटी हुई है। अजित पवार गुट महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे सरकार में शामिल है। खुद अजित पवार राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं। उनके समर्थक के विधायक को में से कुछ को मंत्री भी बनाया गया है। %असली% ह्रष्टक्र तय करने पर चुनाव आयोग की सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शरद पवार जी हमारे साथ खड़े हैं...चुनाव आयोग के समक्ष मुख्य रूप से 2-3 बातें हुई हैं... हमने कहा कि पहले प्राथमिक रूप से हमें सुनें और फिर निर्णय करें कि कोई विवाद है या नहीं...उनकी दलीलों पर सुनवाई अब सोमवार को होगी।

अयोध्या: प्राण प्रतिष्ठा वाली राममूर्ति बनकर लगभग तैयार

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक सात व आठ अक्तूबर को अयोध्या में होगी। बैठक में शामिल होने के लिए राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र समेत अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों का अयोध्या आगमन शुरू हो चुका है। बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर मंथन होगा। रामलला की अचल मूर्ति को लेकर भी बैठक में निर्णय हो सकता है। निर्माणाधीन अचल मूर्ति इसी माह के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। राममंदिर में दो मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। विराजमान रामलला को चल मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाएगा, जबकि अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 51 इंच की अचल मूर्ति का निर्माण रामसेवक पुरम में कर्नाटक व राजस्थान के मूर्तिकार कर रहे हैं। तीन मूर्तिकार अलग-अलग तीन मूर्तियां बना रहे हैं।

जिस मूर्ति में बाल सुलभ कोमलता झलकेगी व राम की मर्यादा के अनुरूप होगी, उसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मूर्ति निर्माण का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह से

अभी जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल

तेहरान । नरगिस मोहम्मदी ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जीता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार उन सैकड़ों-हजारों लोगों को भी पहचान देता है, जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली भेदभाव और धार्मिक शासन की उत्पीड़क नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। ईरान में महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। वह 19वीं महिला हैं, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। बता दें, फिलहाल वे जेल में बंद हैं। नरगिस मोहम्मदी ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जीता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार उन सैकड़ों-हजारों लोगों को भी पहचान देता है, जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली भेदभाव और धार्मिक शासन की उत्पीड़क नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। नोबेल समिति का कहना है कि नरगिस ने महिलाओं की आजादी और उनके हक के लिए कई बार आवाज उठाई है। वो 13 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। समिति ने शांति पुरस्कार की घोषणा ईरान

आंबेडकर के आंसू, गांधी का अनशन, भारत में जातिगत आरक्षण की कहानी

बिहार सरकार द्वारा जारी जाति सर्वेक्षण ने भारत में जाति-राजनीति की गतिशीलता पर एक नई बहस छेड़ दी है। जाति व्यवस्था गहन राजनीतिक बहस और सुधार प्रयासों का विषय रही है। ब्रिटिश काल से लेकर मंडल बनाम कमंडल की राजनीति तक, जाति मुख्य भूमि भारत की सामाजिक-राजनीतिक कथा का केंद्र रही है। दो प्रमुख किरदार जिन्होंने इस विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। भारतीय राजनीति के दो दिग्गज हस्तियों के जाति व्यवस्था पर विचार एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। गांधी ने छूआछूत की निंदा की। उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय में व्यवसाय पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। वह छूआछूत को समाप्त करके और प्रत्येक व्यवसाय को समान दर्जा देकर जाति व्यवस्था में सुधार करने में विश्वास करते थे। दूसरी ओर, स्वयं एक दलित समुदाय से आने वाले बीआर अंबेडकर ने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था अव्यवस्थित है और हिंदू समाज को हतोत्साहित करती है, जिससे यह जातियों के समूह में सिमट कर रह जाता है। अम्बेडकर ने वेदों और धर्मग्रंथों की निंदा की, उनका मानना ??था कि जाति व्यवस्था और छूआछूत हिंदू धार्मिक ग्रंथों की अभिव्यक्तियाँ थीं। उन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में जातिगत असमानता को स्पष्ट किया और जाति उन्मूलन के लिए काम किया। उनका मानना ??था कि जाति पर बनी कोई भी चीज़ अनिवार्य रूप से असमानता पैदा करेगी। जब 1932 में पूना संधि पर हस्ताक्षर किए गए तो उनके परस्पर विरोधी विचार पूरी तरह से प्रदर्शित हुए। गांधी के अथक उपवास ने अंबेडकर को झुकने के लिए मजबूर किया और दलित वर्गों, विशेष रूप से दलितों के लिए एक अलग चुनावी प्रक्रिया की अपनी इच्छा को त्याग दिया।

दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग और बापू का अनशन

17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कमिनुअल अवॉर्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। इसके साथ ही दलितों को दो वोट के साथ कई और अधिकार मिले। दो वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित एक वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते

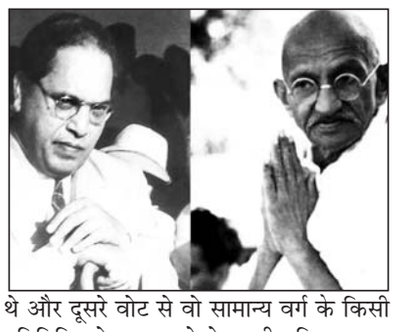

थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। यानी यदि यह लागू हो जाता तो संभवत: दलितों को हमेशा के लिए औपचारिक तौर पर हिन्दुओं से अलग पहचान मिल जाती। राजमोहन गांधी की पुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग दी फाउंडिंग फादर्स' के अनुसार महात्मा गांधी दलितों को दिए इन अधिकारों के विरोध में थे। महात्मा गांधी का मानना था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। महात्मा गांधी दलितों के उत्थान के पक्षधर थे लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और उनके दो वोट के अधिकार के विरोधी थे। महात्मा गांधी को लगता था कि इससे दलित हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे। हिंदू समाज और हिंदू धर्म विघटित हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दलितों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान की बाजी लगा देंगे।

मुझे सड़क के चौराहे पर लटका दें...

जल्द ही अम्बेडकर पर दबाव बढ़ने लगा। अखबारों ने गांधी के गिरते स्वास्थ्य पर दैनिक बुलेटिन प्रकाशित किए और कांग्रेसी गांधी की मांगों पर सहमत होने के लिए अंबेडकर के पास आने लगे। अम्बेडकर पर दबाव अत्यधिक था।

24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उस समझौते से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और दो वोट का अधिकार खत्म हो गया। उसके बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18 फीसदी करने का प्रावधान किया गया। इस समझौते की सबसे अहम बात यह थी कि सिविल सर्विसेज में दलित वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी हो गई। यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान इसी पैक्ट की देन है।

भाजपा सरकार बनने पर कोरबा में एक-एक घरों को चिन्हाकित कर देंगे स्थाई पट्टा: लखनलाल

कोरबा। कोरबा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी लखन लाल देवांगन लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं बाकी मोंगरा क्षेत्र के आनंद नगर बस्ती में गली गली आम जनमानसों से जनसंपर्क कर आशीर्वाद लिया।

उन्होंने जनताओं से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने और कोरबा में भाजपा का कमल खिलने पर पूरे कोरबा विधानसभा के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले सभी को स्थाई पट्टा देने का भरोसा दिलाया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को पक्का मकान ;ग्रामीण एवं शहरी बनाने की बात कही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने पुरे प्रदेश में 16 लाख से अधिक गरीबों के प्रधानमंत्री आवास को छीना। कांग्रेस केवल गरीबों के साथ छलावा करती है। चावल में घोटाला किया, कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, गोठान में घोटाला, पीएससी में घोटाला कर जनता जनार्दन का शोषण किया और छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। कोरबा में खुलेआम अवैध वसूली रेत में वसूली, डामर घोटाला, कोयला में प्रतिटन अवैध वसूली, इस तरह से कांग्रेस का कारनामाए झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ बनाने के साथ पीछे धकेल दिया।

कोरबा की जनता सब समझती है ऐसी भ्रष्टाचार निकम्मी सरकार को उखाड़ कर सड़क में फेंक देगी। इस अवसर पर भाजपा के जिला पदाधिकारी कार्यकर्ता महिला मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी सहित अनेको स्थानीय लोग उपस्थित थे।

चंद्रा समाज के लिए बनेगा सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन

चंद्रा समाज का सामाजिक मिलन समारोह कोरबा के पोड़ीबहार में आयोजित हुई। कार्यक्रम में पूर्व महापौर कोरबा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन विशेष रूप से सम्मिलित हुए। सामाजिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए लखन लाल देवांगन ने कहा कि सामाजिक सम्मेलन से निश्चित ही समाज की एकजुटता के साथ भाईचारा बनी रहती है। चंद्रा समाज भी आज सभी क्षेत्रों में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चंद्रा समाज के लोग सीधे और सरल स्वभाव के हैं। मैं समाजजनों से परिचित हूं समाज के लोगों से मेरा बेहद करीबी सम्बन्ध है। समाज के लोगों से कोरबा विधानसभा में भाजपा के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। विधानसभा चुनाव में भरपूर आशीर्वाद मिले। समाज के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। समाज के लोग जनबल का साथ दे तथा धनबल को मात दे। इस अवसर पर डॉ राजीव सिंह जिलाध्यक्ष भाजपा कोरबा, कृष्ण कांत चन्द्रा पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष चन्द्रा समाज एवं भाजपा जिलाध्यक्ष सक्ती, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ जे पी चंद्रा, अशोक चावलानी, अश्वनी चन्द्रा आदि उपस्थित थे।

जंगली हाथियों का आतंक, कटघोरा-अंबिकापुर एनएच आधे घंटे तक जाम

कोरबा। कोरबा के कटघोरा वनमंडल में हाथियों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। जिसके कारण वन विभाग के साथ ही ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगली हाथियों का दल एक बार फिर से जंगल से निकलकर कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गया। करीब 45 हाथी ग्राम चोड़धवा के पास पहुंच गए। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब आधे घंटे तक अवागमन बाधित रहा।

कोरबा जिले के कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम चोड़धवा के पास वाहनों के पहिए उस वक्त थम गए जब जंगल से निकलकर हाथियों का दल बीच सड़क पर पहुंच गया। हाथियों को देखते ही वाहन अपने आप रुक गए और करीब आधे घंटे तक मार्ग पूरी तरह से जाम रहा। 45 हाथियों केदल में कई बेबी एलिफेंट भी मौजूद थे। इस कारण लोगों ने किसी तरह का रिस्क नहीं लिया। वाहन जहां तहां फंसे रहे। मुख्य मार्ग पर हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिती को अपने नियंत्रण में लिया। हाथियों के जंगल जाते ही फिर से मार्ग पर यातायात व्यवस्था बहाल हो सका।

नेशनल हाईवे पर हाथियों का आना कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हाथी कई बार नेशनल हाईवे पर आ चुके हैं। जिसके चलते आवाज आए काफी समय तक बाधित रही।

कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि हाथियों का दल पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। लगातार हाथियों पर नजर रखी जा रही है। सूचना मिलते ही रेंजर समेत वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आवाज ही कर रहे लोगों को रोका गया। जहां रिस्क कर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया।

ग्रामीणों के थाने घेराव के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ा

राजनांदगाव। शहर के लालबाग थाने का देर रात सैकड़ों ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। देर रात महिलाओं भी काफी संख्या में थाने पहुंच गई। इस दौरान काफी हंगामा और नारेबाजी हुई। पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई। देर रात तक ग्रामीण थाने के पास ही डटे रहे।

घुरदा में खदान के जमीन के रास्ते को लेकर बीते दिनों विवाद हुआ था। सीमांकन को लेकर ग्रामीणों ने असहमति जताई थी। इस दौरान चक्काजाम की स्थिति भी बनी थी। शासन के सीमांकन का उल्लंघन कर ग्रामीणों ने वहां सड़क खोद दी। गड्ढे भी कर दिए। जिसके बाद मामले में स्रङ्कक्र की गई, गांव के कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस गांव के दो आरोपी युवकों को पकड़कर थाने लेकर पहुंची थी। इसके कुछ ही देर बाद युवकों के परिजन और ग्रामीण थाने पहुंच गए। युवक को छोड़ने की मांग करते हुए थाने का घेराव कर दिया। पुलिस के बड़े अधिकारी और एसडीएम को देर रात लालबाग थाने पहुंचना पड़ा।

एसडीएम अरुण वर्मा ने कहा सीमांकन एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के अंदर भूमि का मापन होता है। कई बार इससे कई लोग संतुष्ट नहीं होते तो ऐसे में उन्हें कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। ग्रामीणों को समझाया है। सभी माने और वापस गांव चले गए हैं। एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने कहा खदान के जमीन के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। जिस पर स्टे लगा हुआ है। इसी संबंध में जांच में युवकों को लाया गया था। मुचलके पर छोड़ दिया गया है।

अधिकारियों को देखने के बाद ग्रामीण और भड़क गए। हंगामा और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों को समझाइश दी गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवकों को मुचलके पर रिहा कर दिया। तब कहीं जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ।

विधायक रंजना साहू ने किया आमदी में विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

धमतरी। धमतरी विधानसभा के नगर पंचायत आमदी में विधायक रंजना डीपेंद्र साहू के करकमलों से वार्डों में नाली व सीसी रोड निर्माण के लिए एक करोड़ 88 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन महाराज जी के मंत्रोपचार के साथ विधि विधान से समस्त पार्षद गण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त वार्ड वासियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। साथ ही विधायक निधि से स्वीकृत हृदय स्थल बाजार चौक में शेड निर्माण कार्य, एवं किचन शेड निर्माण कार्य 13 लाख के विकाश कार्यों का लोकार्पण किया गया। समस्त नगर पंचायत वाशियो ने सभी अतिथियों का स्वागत किए । स्वागत उद्बोधन में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमंत माला ने बताया की नगर पंचायत आमदी के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, और क्षेत्र की विधायक रंजना साहू ने अपनी जन्मभूमि के लिए अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृति हमारे नगर पंचायत को दिए हैं, उनका प्रयास नगर के विकास के लिए रहा समस्त नगर पंचायत की ओर समय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम के उद्बोधन में विधायक रंजना साहू ने कहा कि विकास कार्य, मूलभूत सुविधाएं देना जनप्रतिनिधि का दायित्व है किंतु हुए निर्माण कार्य को सहेजने और संवारने का कार्य स्थानियों का होता है। जनहित के लिए किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता किंतु उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब उनका सदुउपयोग हो। लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में तेजराम साहू उपाध्यक्ष नगर पंचायत आमदी, उमानंद कुंभकार

सभापति, कोमल यादव सभापति, लेखेश्वरी साहू पार्षद, अनीता ठाकुर, पार्षद, गजेंद्र प्रजापति पार्षद, घनानंद साहू पार्षद, कविता साहू पार्षद, व्यास नारायण पार्षद , प्रेम साहू पार्षद , लक्ष्मी पटेल पार्षद ,भीखम साहू पार्षद, सुनिता साहू पार्षद, उषा देवांगन पार्षद, एल्डरमेन भागीरथी देवांगन धनीराम साहू, तीरथ साहू, असरु साहू, सुखदेव साहू, बिस्सू पटेल, कार्तिक साहू, शिवप्रशाद, गणेश्वर साहू, जागेश्वर साहू, किशोर कुंभकार, नारायन मटियारा, जागेश्वर ध्रुव, फूलसिंह, राधेश्याम साहू, ज्योति साहू,दीनदयाल, सोनु साहू, कमल साहू, तामेश्वर साहू, निर्मला , प्रमिला, बिसन, जीतेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में नगर पंचायत आमदी के वार्डवासी उपस्थित रहे।

विधायक ने किया बोदाछापर में शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण

ग्राम बोदाछापर में ग्रामीण साहू समाज भवन में विधायक निधि से स्वीकृत शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण विधायक रंजना डीपेंद्र साहू के द्वारा किया गया। सामाजिक पदाधिकारियों के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। अतिथि उद्बोधन में विधायक रंजना साहू ने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना आवश्यक है और नशा पान को समाज से दूर रखना अति आवश्यक है। निर्माण कार्य सतत प्रक्रिया है सामाजिक गतिविधियों के लिए हुए निर्माण कार्यों को सहेज कर रखना सभी का नैतिक दायित्व है। साहू समाज के जिला अध्यक्ष अवनेंद्र साहू ने समाजिक नियमावली पर विचार रखते हुए कहा कि समाज को आगे बढ़ाने और मजबूती के लिए समाज के नियमों की जानकारी सभी को होनी चाहिए, नियमावली समाज के लिए होती है जिसके पालन करने से समाज अधिक मजबूत होता है। धमतरी तहसील साहू समाज अध्यक्ष गोपाल साहू ने ग्रामीण साहू समाज को बधाई दिए और निरंतर विधायक के द्वारा साहू समाज के लिए अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृति दिलाई गई है उसके लिए आभार प्रकट किए। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य रूप से भखारा तहसील उपाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य दमयंती साहू, साहू समाज परिक्षेत्र अध्यक्ष डेरहू राम साहू, भाजपा भोथली मंडल अध्यक्ष हेमंत चंद्राकर, जनपद सदस्य जागेश्वरी साहू, महामंत्री मिस्त्री पटेल, प्रीतम साहू, रुपा नामदेव, ग्रामीण वरिष्ठ पुरुषोत्तम साहू, चोवालाल साहू, रूपचंद साहू, राजू साहू, गोपालराम साहू आदि उपस्थित थे।

गायों की मौत पर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला

धमतरी। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही रायपुर में तोता मेला ग्राउंड में युवा मितान सम्मेलन के दौरान गायों की मौत पर राजनीतिक पार्टियों में जमकर हल्ला हुआ था। अब धमतरी में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। जहां गायों की मौत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है।

एनएच 30 के बाइपास और उसके आसपास गुरुवार को 7 गाय मरी हुई मिली। 3 गाय घायल हालात में मिली। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और गायों को दफनाया। गायों की मौत को लेकर भाजपा ने निगम पर गंभीर आरोप लगाए।

भाजपा ने आरोप लगाया कि पास में ही खपरी गांव में गौठान मौजूद है। लेकिन वहां गायों की कोई देखभाल नहीं की जाती हैं। ना वहां गायों के लिए चारे की व्यवस्था है, ना ही गायों को पीने के लिए पानी मिलता है। जिससे गायों की हालत खराब होती जा रही है और उनकी मौत हो रही है। भाजपा नेता रामु रोहरा का कहना है कि सभी गाय गौठान और कांजी हाउस की है।

इधर नगर निगम मरी हुई गायों को बाहरी बता रहा है। निगम अधिकारी का कहना है कि गौठानों में गायों के लिए पूरी व्यवस्था है। गौठानों में चारा पानी की कोई कमी नहीं है। दिन और रात में पशुओं की देखभाल के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो पशुओ को चराने के लिए ले जाते है और हरा चारा खिलाते है। नगर निगम के उपायुक्त पी सी सार्वा ने बताया कि नेशनल हाईवे में घायल हुए 3 आवारा पशुओं को गौठान में इलाज के लिए लाया गया है। जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि मृत पशु को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गौठान के बाहर रख दिया। इसका पता कराया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो मैराथन का किया आयोजन

बलौदाबाजार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिसकी शुरूआत गुरुवार को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से किया गया। दौड़ में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी। श्रीनिवास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और युवाओं के साथ दौड़ लगाई। दौड़ के बाद विजेता युवाओं को चेक देकर सम्मानित किया। इस मैराथन दौड़ में संसदीय सचिव शकुन्तला साहू, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र बंजारे सहित बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लेकर तीन किलोमीटर की लंबी दौड़ लगाई। श्रीनिवास ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश में फैली नफरत को मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जिसका परिणाम हमें कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला है। आज हम छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज कर रहे हैं।

दर्री जोन में महापौर ने किया विकास कार्यो का भूमिपूजन

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा व दर्री जोनांतर्गत 58 लाख रूपये से अधिक की लागत से विभिन्न वार्डो में 06 विकास कार्यो का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल के द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण एवं एल्डरमेनगण आदि उपस्थित थे। नगर पालिक निगम केारबा के कोरबा एवं दर्री जोनांतर्गत 06 विकास कार्यो का महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं पूर्व महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल के करकमलों से 58 लाख रूपये की लागत वाले विकास कार्यो किया भूमिपूजन। महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि हमारे कोरबा के लाड़ले, दुलारे, लोकप्रिय राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के आशीर्वाद से नगर पालिक निगम कोरबा के सभी वार्डो में विकास की गंगा बह रही है, हमने कोरबा के विकास के लिये सड़क, नाली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यान से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किया है।

छात्रावास की छत से कूद आठ छात्राएं हुईं फरार, मचा हड़कप

कोरबा। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में एक छात्रावास में आज सुबह हड़कंप मच गया। जहां छात्रावास की छत से कूदकर आठ छात्राएं फरार हो गई। इस मामले की जानकारी तुरंत ही छात्रावास प्रबंधन ने कटघोरा पुलिस को दी। जिसके बाद घंटों मशक्त की और तानाखार के पास से सभी बच्चे बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ह्लह्ल के माध्यम द्वारा छात्रावास में 39 छात्राएं पढ़ रही हैं। छात्रावास से घर जाने के लिए सभी छात्राएं भागी थी। यह छात्रावाल कटघोरा के भारत भवन खुटरीगढ़ में संचालित है। स्पायर एनजीओ दिल्ली की कंपनी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को छोड़ चुके बच्चों को पढ़ा रही है।

मैनपुर में 31 नग हीरों के साथ तस्कर गिरफ्तार

गरियाबंद। मैनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 31 नग हीरों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। हीरे की कुल कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी तस्कर कोरबा के बालको का निवासी हैं। आरोपी का नाम छोटेलाल ठाकुर है। आरोपी झरियाबाहरा के पास खड़ा था। जहां वो किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था।इसकी भनक मुखबिर को लगी। इसके बाद उसने पुलिस तक सूचना पहुंचाई जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची आरोपी मौके से भागने लगा। जिसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। मैनपुर थाना प्रभारी ने कहा पकड़े जाने पर आरोपी ने अपना नाम छोटेलाल ठाकुर निवासी बालको कोरबा बताया। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 31 नग हीरे निकले। जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 1 लाख 95 हजार रुपए बताई जा रही है। मैनपुर के पहलीखांड और भेजराड़िही के जंगलों में हीरा खदान है।जहां से तस्कर आसानी से हीरा निकालकर तस्करी करते हैं।

रानी दुर्गावती की जयंती पर विधायक ने किया माल्यार्पण

धमतरी। अद्म्य साहस की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती के जयंती पर उनके शहादत को नमन करते हुए गोकुलपुर वार्ड में रानी दुर्गावती की प्रतिमा में माल्यार्पण करने के लिए विधायक रंजना डीपेंद्र साहू, शहर मंडल अध्यक्ष विजय साहू, पार्षद ईश्वर सोनकर रुपा नामदेव पहुंचे। सर्वप्रथम सभीने पुजा अर्चना कर माल्यार्पण किए। माल्यार्पण कर नमन करते हुए विधायक रंजना साहू ने वीरांगना रानी दुर्गावती को अदम्य साहस एवं शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि जहां आज के आधुनिक युग में महिलाएं नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वहीं वे इतिहास में भी किसी से पीछे नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण वीरांगना रानी दुर्गावती है। जिनके त्याग, साहस एवं बलिदान को आज भी देश सम्मान के साथ याद करते है। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष विजय साहू ने वीरांगना के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महारानी के शासनकाल में ही गोंडवाना राज्य की नींव रखी गई। हमें उनकी ताकत एवं साहस से प्रेरणा लेकर हमें अपना मार्ग प्रसस्त करना चाहिए।

कांग्रेसी कार्यकर्ता रंजना की उपस्थिति में हुए भाजपा में शामिल

■ **हमारे युवा विधायक रंजना साहू की क्षेत्र में सक्रियता से काफी प्रेरित हैं,इनके जुड़ने से दल मजबूत होगा : हेमंत चंद्राकर**

धमतरी। धमतरी विधानसभा के ग्राम बोदाछापर में कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता धमतरी विधायक रंजना साहू ने भाजपा में शामिल हो रहे लोगों को भाजपा गमछा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई।

विधायक रंजना साहू ने बताया कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकारों की योजनाओं से प्रभावित होकर आज सैकड़ों की संख्या में निरंतर अन्य पार्टियों से लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत हो रही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास

के मंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण कार्य मे जनता जुड़ रही है । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, केंद्र में मोदी सरकार की कुशल नेतृत्व और पूर्व में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों एवं योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लक्ष्य मानकर अनेक लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आए हुए नए कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और आगामी चुनाव में जीत दिलाने के लिए कटिबंध होकर काम करें जिससे पुन: केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को हराकर पुन: बीजेपी की सरकार बनाना है। मंडल अध्यक्ष हेमंत चंद्राकर ने कहा कि हमारे युवा विधायक रंजना साहू की क्षेत्र में सक्रियता से काफी प्रेरित हैं, युवाओं के जुड़ने से दल मजबूत होगा। जनता को झूठे वादे नहीं विकास चाहिए, इसलिए भाजपा की सरकार बनाने के लिए जनता ने मन बना लिया और इसीलिए लगातार अन्य पार्टी के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं और कार्यकर्ता निरंतर जुड़ रहे हैं।

कांग्रेस सरकार से त्रस्त होकर भाजपा में शामिल होने वालों में गोपाल साहू, लोमस साहू, कपिल नारायण, चैन सिंह, ज्ञानेंद्र, उदय राम, लखन देवदास, धर्मेंद्र साहू, चोवा राम साहू, भुवन, खेमराज, नोहर, कृष्ण कुमार, भोमेश्वर साहू, रोमन, दानेश्वर साहू, शशिकांत, गोलू, प्रेमलाल, फलित कुमार, श्रीमती मोहनी साहू, सोहागा साहू सहित अन्य लोग जुड़े। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य दमयंती साहू, जनपद सदस्य अवनेंद्र साहू, जनपद सदस्य जागेश्वरी साहू, जनपद सदस्य गोपाल साहू, मंडल महामंत्री प्रीतम साहू, मंडल महामंत्री मिश्री पटेल, रुपा नामदेव उपस्थित रहे।

लक्ष्मी ध्रुव के नेतृत्व में सांकरा में हुआ विकास

नगरी। सिहावा विधानसभा के ग्राम पंचायत सांकरा में ऐतिहासिक विकास हुआ डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने बताया कि विधानसभा के सबसे बड़ा ग्राम पंचायत सांकरा है यहां के जनता को सभी प्रकार के मूलभूत सुविधा उपलब्ध होना चाहिए इसी तारतम्य में हमने ग्राम सांकरा में विकास के कोई कसर नही छोड़ी। 2018 में चुनाव प्रचार के समय सांकरा सभी वार्डो में पदयात्रा किया तब से मैने अपने मन में यह बात ठान ली थी कि यहां विकास की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास नही हुआ वो आज मैने 5 वर्षों में कर दिखाया, वैसा ही प्यार और दुलार मुझको सांकरा ग्राम से मिलता आ रहा है मै हर महीने में कम से कम 02 बार इस पंचायत क्षेत्र का दौरा करती आ रही हूं मेरे को वहां के जनता द्वारा हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आमंत्रित किए और मै उनका आमंत्रण स्वीकार किया और उनके मांगो के अनुरूप हर समय घोषणा किया मैं

सांकरा ग्राम पंचायत के विकास के बारे में बताना चाहूंगी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रीपा सांकरा में स्वीकृत करवाया, भीमादेव गौठान में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य की स्वीकृति, शासकीय अस्पताल सौंदर्यीकरण पेवर ब्लाक, कांक्रीटीकरण एवं नाली निर्माण तथा 4 नग आवास निर्माण, साहू समाज सामुदायिक भवन का निर्माण, शमशानघाट मे मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण, शमशान घाट तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण, कोरमुड़पारा में सामुदायिक भवन निर्माण, कोरमुड़पारा प्राथमिक शाला में 3 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, कोरमुड़पारा में पानी टंकी का निर्माण, शंकर नगर में 24 लाख का सी.सी. रोड निर्माण, कोरमुड़पारा में रंगमंच जीर्णोद्धार, सामुदायिक भवन निषाद समाज का निर्माण, अटल बाजार के पास शौचालय निर्माण, स्कूलपारा में शेड निर्माण, महावीरपारा में सी.सी. रोड निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि कार्यों की स्वीकृति हुआ है।

बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकारः साव

रायपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज मुंगेली जिले के लोरमी दौरे पर रहे, जहां नगर क्षेत्र में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जगह-जगह भव्य स्वागत किया. उन्होंने मानस मंच में किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान साव ने विधायक एवं सांसद निधि से लाखों रुपए के स्वीकृत कई समाज के भवन सहित प्रेस क्लब लोरमी का भूमिपूजन किया.

इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया के सवाल पर कहा, इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ बनेगी. इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रियंका गांधी के छत्र दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा, उत्तरप्रदेश जाकर वो कहती हैं, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं. प्रियंका गांधी यहां क्यों नहीं लड़ रही. जब रायपुर एडिशनल कार्यालय के पार्किंग में 6 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, रक्षाबंधन के दिन दो बहनों के साथ सामूहिक घटना होती है. शिक्षक दिवस के दिन बस्तर में एक शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार होता है. प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया.साव ने कहा, कांग्रेस सरकार की योजनाएं जैसे होल्डिंग विज्ञापन में दिखता है. उनके नेता कहते हैं कभी 75 पार तो दूसरा नेता 80 पार कहते हैं और यदि राहुल गांधी आएं तो वो बोलेंगे 90 पार, इनके ये सब दावे हवा में रहने वाले हैं. जैसे इनकी योजनाएं और काम है. इस दौरान विधायक धर्मजीत सिंह, पूर्व विधायक तोखन साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता सहित तमाम पदाधिकारी प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए. अरुण साव ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार है. छत्तीसगढ़ में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है. कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है. बिलासपुर के एक कांग्रेसी नेता शेरु असलम खुलेआम कुछ दिनों पहले जमीन मामले में किसान को धमकाते हुए नजर आये थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था. इसके बाद वही कांग्रेस नेता बेख़ौफ़ गोली चलाते हुए नजर आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना कई सवालों को जन्म दे रहा है. हालांकि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में कांग्रेसी जमकर गुंडागर्दी कर रहे हैं.अरुण साव ने बीजेपी के विधायक प्रत्याशियों की वायरल सूची को लेकर कहा कि अभी पार्टी ने दूसरी सूची जारी नहीं किया है कि कौन किस विधानसभा से प्रत्याशी होंगे. दूसरी सूची जल्द ही जारी हो जाएगी. इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस विधानसभा से कौन विधायक प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतारे जायेंगे.लोरमी विधानसभा से अरुण साव का नाम तय होने की सूची सोशल मीडिया में इन दिनों तैर रही है, जो चर्चा का विषय है. इसके सवाल पर अरुण साव ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी की तरफ से अब तक अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी नहीं की है. मुझे उम्मीद है कि जब घोषित होगी तो वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कहां से भाजपा के विधायक प्रत्याशी होंगे.

सीबीसी ने राज्य युवा उत्सव में लगाई चित्र प्रदर्शनी, बताई केंद्र सरकार की नौ साल की उपलब्धियां

रायपुर। भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय परिसर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नौ साल के तहत केंद्र सरकार की विगत 9 वर्ष की उपलब्धियों पर भव्य दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 05-06 अक्टूबर को किया गया। प्रदर्शनी को देखने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवायकेएस) द्वारा आयोजित युवा उत्सव के लिए आए प्रदेश के सभी प्रखंडों के युवा व विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जुटे। इस संबंध में प्रदर्शनी के आयोजक सीबीसी रायपुर के कार्यालय प्रमुख शैलेष फाये ने बताया कि प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 10 प्रमुख उपलब्धियों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, नल-जल योजना, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सर्जिकल स्ट्राइक, गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया आदि को 56 पैनल्स के जरिए दर्शाया गया है। इसी स्थान पर विभाजन की विभीषिका को भी प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी स्थल पर शुक्रवार को राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय का आगमन हुआ। सांसद ने प्रदर्शनी के लिए सीबीसी के प्रयासों की सराहना की।

सांसद संतोष पांडेय ने शुक्रवार को प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत नौ वर्षों में देश के कल्याण के लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं। प्रदर्शनी में सभी विषयों को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने युवा उत्सव में आए प्रदेश भर के युवाओं से प्रदर्शनी देखने व योजनाओं के बारे में जानकारी लेने की अपील की। उन्होंने विभाजन की विभीषिका संबंधी प्रदर्शनी का विशेष तौर पर उल्लेख किया। सांसद ने कहा कि युवाओं को महसूस करना चाहिए कि देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार योगदान दिया।

संक्षिप्त समाचार

कांकेर पहुंचने पर प्रियंका गांधी का आत्मीय स्वागत

कांकेर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रीमती प्रियंका गांधी के भानुप्रताप देव कॉलेज मैदान, गोविंदपुर कांकेर स्थित हेलीपैड पहुँचने पर हेलीपैड में विधायक श्री शिशुपाल सोरी, श्रीमती सावित्री मंडावी, अनूप नाग सहित जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आमजनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। श्रीमती प्रियंका गांधी आज अपने कांकेर प्रवास के दौरान जनरल गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं से मिली। हॉस्टल की छात्राएं बड़े उत्साह से श्रीमती गांधी से मिली। इस अवसर पर श्रीमती गांधी ने छात्राओं से उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर बातें की और उनके साथ सेल्फी भी खिंचाई।

मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में स्वामी आत्मानंद की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भावधारा को छत्तीसगढ़ की जमीन पर साकार किया और मानव सेवा व शिक्षा संस्कार की अलख जगाई। स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी आत्मानंद जी पर भी गहरा असर हुआ, जिससे उन्होंने अपना पूरा जीवन दीन-दुखियों की सेवा में बिता दिया। मठ और आश्रम स्थापित करने के लिए एकत्र की गई राशि उन्होंने अकाल पीड़ितों की सेवा और राहत काम के लिए खर्च कर दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद जी का समाज सुधारक और शिक्षाविद् के रूप में छत्तीसगढ़ में बड़ा योगदान है। उनके मानव सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्य अनुकरणीय और प्रेरणास्पद है।

गोबर्धन पूजा और भाईदूज की छुट्टी घोषित

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। भूपेश सरकार ने गोबर्धन पूजा और भाई दूज की स्थानीय अवकाश का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 13 नवंबर 2023 गोबर्धन पूजा और 15 नवंबर 2023 को भाईदूज की छुट्टी घोषित की है।

भाजपा का प्रियंका से सवाल, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, का नारा क्या सिर्फ जुमला है

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री लता उसेण्डी ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की असुरक्षा तथा मासूम बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं के साथ हो रहे अनाचार, सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को लेकर मुँह में दही जमाए बैठी कांग्रेस महासिचव प्रियंका वाड्रा पर करारा तंज कसा है। सुश्री उसेण्डी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की भाषा बोल रही हैं। जहां से फर्जी आँकड़े भूपेश बघेल को मिलते हैं, वहीं से मिले आँकड़े गिनाकर प्रियंका छत्तीसगढ़ को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुश्री उसेण्डी ने प्रियंका वाड्रा को याद दिलाया है कि फरवरी में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में हुआ था, तब उनके (प्रियंका वाड्रा के) सचिव ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करते हुए कांग्रेस की ही दलित महिला नेत्री से अभद्र व्यवहार किया था। इसकी शिकायत उनके पिताजी ने दर्ज भी कराई थी। नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण संबंधी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराया। इसकी बधाई देने जब उक्त दलित महिला नेत्री दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पहुंची तो फिर कांग्रेस के लोगों ने उनसे अभद्रता की। सुश्री उसेण्डी ने प्रियंका वाड्रा से सवाल किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा क्या सिर्फ जुमला है या फिर यौन उत्पीड़ित दलित महिला नेत्री को न्याय दिलवाएंगीं और अपने सचिव को सजा दिलवाएंगीं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका पर महिलाओं के उत्पीड़न, उनके साथ छलावा व धोखाधड़ी, वहशियाना बलात्कार, हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते हुए सुश्री उसेण्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है तो प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लड़ना चाहिए कि किस बात के लिए वे भरोसे का सम्मेलन, महिला समृद्धि सम्मेलन जैसी सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं? प्रियंका वाड्रा अपने मुख्यमंत्री से महिलाओं के हक में लड़ें। छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक में लड़ें। उन गरीबों के हक में लड़ें, जिनका आवास और अन्न छीना गया है। वे लड़ सकती हैं और भूपेश बघेल यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि ऐ लड़की, नेतागिरी मत कर! रही बात गैस सिलेंडर की तो वह मुख्यमंत्री बघेल से जवाब तलब करें कि वे चार सिलेंडर कहां हैं, जो 2018 के जन घोषणा पत्र में कांग्रेस दे रही थी।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुश्री उसेण्डी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का कोरा जुबानी जमाखर्च करते-करते छत्तीसगढ़ में सुपर सीएम बनाने वाले मुख्यमंत्री बघेल से महिलाओं की दयनीय दशा पर चर्चा करनी चाहिए। गंगाजल की कसम खाकर किए गए शराबबंदी के वादे को दरकिनार कर महिलाओं से विश्वासघात किया गया। तेंदूपत्ता बीनने वाली महिलाओं की चरण पादुका तक कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छीन ली।

कांग्रेस सरकार के उत्पीड़न से उपजे युवाओं के आक्रोश पर भाजपा ने पूछे 6 सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेरोजगारी जैसे संवेदनशील मसले पर भी संजीदा नहीं है और युवा बेरोजगारों और उनके परिवारों के स्वप्नों को कुचलकर उनके सुनहरे भविष्य को हताशा-निराशा की गहन अंधी खाइयों में धकेलकर राजनीतिक मिथ्याचार का पोषण करने में लगी है। श्री चंदेल ने कहा कि हाल ही पीएससी भर्ती परीक्षा में सामने आईं गड़बड़ियों से भी साबित हुआ है कि प्रदेश सरकार हर जगह घपले करके भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के अवसरों की ताक में रहती है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार को जब-जब उसका वादा याद दिलाया गया, प्रदेश सरकार ने तब-तब बेरोजगारों पर लाठियाँ बरसाईं। बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर प्रदेश सरकार जिस तरह के रोज नये शिगूफा छोड़ रही है, प्रदेश का युवा उससे बेहद संत्रस्त है, और यक़ीनन समय आने पर वह इस सरकार को माकूल जवाब देगा। श्री चंदेल ने प्रदेश में बेरोजगारी और युवाओं के साथ छलावे से उपजे युवा आक्रोश के मद्देनजर प्रदेश की भूपेश सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए हमला बोला और प्रदेश सरकार से इन सवालों का जवाब मांगा है =

1. छत्तीसगढ़ के युवाओं का 15 हजार करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता प्रदेश की भूपेश सरकार कब देगी?
2. प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में हुई 26 हजार आत्महत्याओं में 18 हजार से ज्यादा आत्मगत्या युवाओं ने की है। आखिर युवा प्रदेश सरकार की नीतियों से इतना निराश क्यों है?
3. प्रदेश के मेहनतकश युवाओं के भविष्य के साथ पीएससी घोटाला करके प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र तक में भ्रष्टाचार किया गय। इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं?
4. 200 फूड प्रोसेसिंग युनिट लगाकर बेरोजगारों, विशेषकर किसानों के बेटों को रोजगार दिया जाना था। पिछले विधानसभा चुनाव में के गए इस वादे का क्या हुआ?
5. आज भी प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन्हें रोजगार देने में विफल क्यों रही है?
6. प्रदेश में निवेश के माध्यम से नए रोजगार का सृजन कर प्रदेश की हुनरमंद तरुणाई को आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन के अवसर देने में विफल क्यों है?

ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन संरचना के संबंध में आदेश जारी

■ मुख्यमंत्री की घोषणा पर हुआ अमल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र में की गई घोषणा पर अमल करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के स्वीकृत मानदेय/वेतनमान के संबंध में 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव को (3500-10000+1100 ग्रेड वेतन तथा 4000 रूपए विशेष भत्ता, 15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव को (5200-20200+2400 ग्रेड वेतन तथा 3000 रूपए विशेष भत्ता दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेण्डर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश, 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिवस तक के लिये मातृत्व अवकाश (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के छ माह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है। पुरूष ग्राम पंचायत सचिव जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश (बच्चे के जन्म के 15 दिवस पहले से लेकर छ: माह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।

05 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को उनके सेवानिवृत्त होने पर, अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छ:माही समयावधि के लिए, उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के अध्याधीन रहते हुये, उन्हें उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा। 05 वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् यदि सेवा में रहते हुए, किसी पंचायत सचिव की मृत्यु हो जाती है, तो उपादान की धनराशि उसकी कुल अंतिम उपलब्धियों के 10 गुना के बराबर अथवा खण्ड (क) के अधीन निश्चित की गई धनराशि, जो भी अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। खण्ड (क) और (ख), दोनों के लिये देय उपादान राशि 10.00 लाख रूपये से अनाधिक होगी।

ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह सुविधा शासन द्वारा समय-समय पर अद्यतन की गई मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में, अंतः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु ही प्रदाय की जाएगी। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 05 लाख रूपये होगी। इसकी विस्तृत प्रक्रिया पृथक से जारी की जायेगी। यह आदेश 01 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील होगा।

भाजपा की सलाह, प्रियंका 'भू-पे एप' जरूर देखें

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और आईटी सेल के प्रभारी दीपक म्हस्के ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा को भाजपा द्वारा गुरुवार को लॉन्च किया गया भू-पे एप देखने की सलाह दी है। श्री म्हस्के ने कहा कि इस एप का लिंक भी प्रियंका वाड्रा को भेजकर उन्हें भू-पे एप ज़रूर देखने की बात कही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री म्हस्के ने कहा कि एप के लॉन्च होते ही केवल एक ही दिन में 50 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे देखा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की पूरी जनता भी इसे देखेगी। यह ऐप सोशल मीडिया में वायरल है। श्री म्हस्के ने कहा कि इस भू-पे एप में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार का काला चिठ्ठा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कैसे-कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, यह देखिए। इससे कांग्रेस नेतृत्व को भी फायदा होगा, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी हिसाब मिल जाएगा कि भ्रष्टाचार का पैसा ऊपर तक ठीक से पहुंचा है कि नहीं? कहीं भ्रष्टाचार में भी तो भूपेश सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? श्री म्हस्के ने मुख्यमंत्री बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस की इस सरकार ने लगातार धोखा किया है, झूठ बोला है। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के रग-रग में समाया हुआ है, इससे कांग्रेस के क्षत्रप अछूते कैसे रह सकते हैं?

नारों से लेकर भाषण तक नेता कर रहे छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों छत्तीसगढ़िया होने की जंग छिड़ी हुई हैं। राज्य के दोनों ही प्रमुख दल प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार आने के बाद प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा मिला है तो भाजपा कह रही है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद शुरू से रहा है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि हाल फिलहाल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर चर्चा सुनने को मिल रही है यह पहले नहीं देखा। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दौरे पर आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी मतदाताओं से वोट डालने के लिए छत्तीसगढ़ी में स्लोगन दिया है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इन दोनों छत्तीसगढ़ी में स्लोगन, नारे और भाषण राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं।

चुनावी राज्य होने के कारण आए दिन बड़े बड़े बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित करने के दौरान सबसे पहले छत्तीसगढ़ी में ही संबोधित कर रहे हैं। हाल ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायगढ़ दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी के साथ अपना संबोधन शुरू किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा की छत्तीसगढ़ के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। अऊ नई सहिबो,बदल के रहिबो। जुलाई में छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान मोदी ने रायपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बदलबो-बदलब, ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलबो'। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महातारी, माता बम्लेश्वरी, दंतेश्वरी, महामाया, बाबा गुरु घासी दास, के पावन धरा ले आप सब्बा दाई दीदी, भाई बहिनी संगी साथी मन ल मोर जय जोहार।

प्रदेश में बढ़ रहे छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा का क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार आने के बाद प्रदेश में लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, बोली, खान पान को लेकर काम किया गया है। तीज त्योहारों को महत्व दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ी तीज त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन हो रहा है जो भाजपा के 15 साल के शासन काल में कभी देखने को नहीं मिला।

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा आज बीजेपी छत्तीसगढ़ भाषा में बात करने को मजबूर हुए हैं। ठेठरी, खुरमी खाने के लिए मजबूर हुए हैं। यह भूपेश सरकार के द्वारा किए गए काम का ही नतीजा है। अगर इन्होंने छत्तीसगढ़िया बात को लेकर काम किया होता तो आज 15 सीटों पर सीमित नहीं रह जाते।

भाजपा का कहना है कि हर राज्य की एक अपनी बोली, भाषा होती है। उसका इस्तेमाल स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली का महत्व है। यह सहज और सरल है। इसका उपयोग किया जाता है लेकिन कोई पार्टी इसका एकाधिकार करती है तो वह गलत होगा। कांग्रेस क्षेत्रवाद के आधार पर दूसरों को बांटने का काम करती है। इस दौरान भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस को चुनौती भी दे दी। उन्होंने कहा जिस मंच पर आकर चर्चा कर ले हम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ियों के लिए हमने क्या नहीं किया है। यह कौन ठेकेदार होते हैं।

जल ही जीवन है....

(See Para 2.079 & App. 2.10-A of W.D. Manual)

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.)

निविदा सूचना क्र.11/ व.ले.लि. / 2023-24 दि. 03/10/2023

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण)

निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु मुहरबन्द निविदाएँ फार्म-बी (आयटम रेट प्रपत्र) में छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग के दिनांक 01/08/2010 से प्रभावशील एवं प्रचलित **एस.ओ.आर.0 को दिनांक 22.08.2022 से संशोधित दर पर अथवा इससे कम दरों** पर एकीकृत पंजीयन प्रणाली द्वारा सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नाम से दिनांक 13-10-2023 तक मैन्यूअल पद्धति से कार्यालयीन समय में आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में सभी आवश्यक शर्तें विक्रय हेतु उपलब्ध निविदा प्रपत्र में दी गई है।

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि रू. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि	सक्षम श्रेणी
1	3	4	5	6	7	8
1.	गरियाबंद जिले के डोकरेल व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर कार्य के शेष मिट्टी कार्य	रू. 14.54 लाख	Rs.11,000/-	रू. 750/-	03 माह वर्षाकाल सहित	एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत 'डी' श्रेणी एवं ऊपर

निविदा प्रपत्र एवं निविदा से संबंधित अन्य विवरण संबंधी जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद के कार्यालय में दिनांक 13.10.2023 तक कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिन को छोड़कर) प्राप्त कर सकते है तथा निविदाएँ दिनांक 18.10.2023 को कार्यालयीन समय तक अर्थात् अपरान्ह 5.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद में मात्र रजिस्ट्रेर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम, जैसे व्यक्तिगत डिलीवरी, कुरियर सेवा इत्यादि से प्राप्त नहीं की जावेगी।

इच्छुक निविदाकार कार्य से संबंधित विस्तृत विवरण प्राप्त करने या कार्यस्थल का निरीक्षण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग देवभोग अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकते है।

निविदाएँ दिनांक 19.10.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद में उपस्थिति निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, जो भी उपस्थित रहना चाहें, के समक्ष खोली जायेगी । बयाने की राशि कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद के नाम से जमा की जावेगी ।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग गरियाबंद
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

जी-06064/4

जातीय जनगणना, यूपी बनेगा सियासी अखाड़ा

अखिलेश वाजपेयी

इसे संयोग ही कहा जाएगा कि 90 के दशक में बिहार की भूमि पर घटित एक घटना ने हिन्दुत्व की राजनीति को धार दी थी। उस समय रामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए निकली रामरथयात्रा को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक दिया था। इसकी प्रतिक्रिया ने हिन्दुत्ववादी राजनीति को नयी धार दे दी।अब लगभग साढ़े तीन दशक बाद लालू के पुत्र तेजस्वी और नीतीश कुमार की संयुक्त सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर भाजपा को एक बार फिर प्रखर हिंदुत्व का कार्ड खेलने का मौका दे दिया है। इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित सभा से दे भी दिया है। भाजपा एक ओर जहां केन्द्रीय स्तर पर हिन्दुत्व को मुद्दा बनायेगी, वहीं स्थानीय सरकारों के सामने गरीबी का मुद्दा उठायेगी। इस तरह जातिवादी राजनीति की काट के तौर पर भाजपा हिन्दुत्व के साथ अंत्योदय का प्रयोग करने के लिए तैयार हो रही है। छत्तीसगढ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं तथा गरीबों को बांटकर देश को तबाह करने का आरोप लगाया। मोदी ने गरीबों के कल्याण को मुद्दा बनाया और कहा कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। उन्होंने आबादी के हिसाब से हक देने की बात पर कांग्रेस की अल्पसंख्यक नीति पर प्रहार किया और कहा कि %कांग्रेस आबादी के हिसाब से हक देने की बात कहकर क्या अपने उस एजेंडे से पलट रही है जिसमें उसने देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का बताया था। अगर आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए तो क्या हिंदुओं को आगे आकर सभी हक ले लेना चाहिए।% साफ है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने एजेंडा तय कर लिया है। भाजपा के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि %भाजपा जातीय जनगणना की विरोधी नहीं है लेकिन विपक्ष की तरह हमारा मकसद गरीबों को जातियों में बांटकर उनको बरगलाना नहीं है। हमारे लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है। हम समाज में बिना संघर्ष पैदा किए सबके कल्याण के लिए काम करना चाह रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में ही केंद्र में सरकार संभालते ही सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास-सबका विश्वास के मंत्र पर विकास की रूपरेखा तय कर दी थी। उनका कहना है कि भाजपा लोगों को याद दिलाएगी कि जाति जनगणना के नाम पर लोगों को बरगलाने वालों का मकसद उनका कल्याण नहीं बल्कि भाजपा सरकार के कल्याणकारी कार्यों में रोड़े डालकर गरीबों को उनके हक से वंचित करना है। आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषक प्रो. ए.पी. तिवारी की बात भी भाजपा नेता की बातों की पुष्टि करती है। प्रो. तिवारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लगभग साढ़े नौ साल और योगी के लगभग साढ़े छह साल के शासन में गरीब कल्याण योजनाओं, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, नीट में पिछड़ों को आरक्षण, प्रधानमंत्री आवास, चिकित्सा के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी तमाम योजनाओं के सहारे सरकार ने करोड़ों शोषित व वंचित परिवारों से सीधे संवाद व संपर्क स्थापित कर लिया है। जाति जनगणना जैसे दांव की काट भाजपा इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों की लामबंदी से करेगी। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। दरअसल, भाजपा ने अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए आरक्षण में अलग आरक्षण देने का प्रयोग यूपी में किया था। मतलब पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को मिले आरक्षण का बड़ा हिस्सा हथियाने के विरोध की आवाज कोई 23 साल पहले यूपी में भाजपा ने ही उठाई थी। भाजपा की तरफ से ही नहीं अति पिछड़ी जातियों के संगठनों की तरफ से भी लगातार सपा पर अति पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगता रहा है।

चीन से चंदा और भारत विरोधी धंधा

आशीष कुमार अंशु

एक समय था, जब अलग अलग लॉबी से जुड़े एजेन्ट अपना सवाल संसद की चर्चा में शामिल कराने के लिए सांसदों को पैसे देते थे। वर्ष 2005 में संसद में धन लेकर सवाल पूछने के आरोप में 10 लोक सभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद को दोनों सदनों ने बर्खास्त कर दिया था। समय बदला और समाज-सरकार को प्रभावित करने का ढंग भी। अब सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। किसी समाचार पत्र अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया को नियंत्रित करने के मुकाबले किसी यूट्यूबर अथवा वेबसाइट के माध्यम से अपना एजेन्डा प्रचारित प्रसारित करना कम खर्चीला और सुरक्षित निवेश बन गया है लेकिन यह सुरक्षित निवेश जब देश की संप्रभुता के लिए ही खतरा बन जाए फिर चिंता की बात है।

न्यूजक्लिक नामक न्यूज पोर्टल का विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला कुछ ऐसा ही है, जहां चीन के प्रोपगेंडा को भारत में चलाने के लिए 38 करोड़ रुपए लिए गए। अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। सात दिनों के लिए उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा गया है। उनके ऊपर आरोप गंभीर हैं। न्यूजक्लिक पर आरोप है कि चीन समर्थित अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम और न्यूजक्लिक पोर्टल के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के बीच इस मुद्दे पर ईमेल चैट हुई थी कि कश्मीर और अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं हैं, इस एजेन्डा को सेट करना है। लेफ्ट इको सिस्टम के माध्यम से इसे मुद्दा बनाना है। मिल रही जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच ईमेल में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि भारत के नक्शे को किस तरह से बनाया जाये कि उसमें से कश्मीर और अरुणाचल को विवादित घोषित कराया जा सके।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के अन्तर्गत न्यूजक्लिक का मामला दर्ज किया है। 03 अक्टूबर की सुबह न्यूजक्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के घर पर छापेमारी शुरू हुई। शाम होते-होते दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों ने दिल्ली में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया। उधर मुंबई पुलिस के अधिकारी एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के आवास पर पहुंचे थे। तीस्ता के पति जावेद का संबंध भी न्यूजक्लिक के साथ रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। न्यूजक्लिक से जुड़े 37 पुरुष संदिग्धों और 9 महिला संदिग्धों से उनके आवास पर पूछताछ की गई। जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें औनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, सोहेल हाशमी, भाषा सिंह, उर्मिलेश यादव, परंजॉय गुहा ठाकुरता के नाम प्रमुख हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजक्लिक के माध्यम से अभिसार शर्मा को 45 लाख रुपए, परंजॉय गुहा को 40 लाख, उर्मिलेश यादव को 23 लाख, तीस्ता के पति जावेद आनंद को 13 लाख रुपए चीन से आए फंड में से मिले थे।

न्यूजक्लिक पर हुई कार्रवाई कोई आनन-फानन में हुई कार्रवाई नहीं है। वेबसाइट की फंडिंग से जुड़ी जांच लंबे समय से चल रही थी। 03 अक्टूबर की छापेमारी से पहले स्पेशल सेल की बैठक दो अक्टूबर को हुई थी। बैठक में स्पेशल सेल के अधिकारी थे। वहां पूछताछ की रूपरेखा तैयार हुई, जिनके यहां रेड डालनी थी, उनकी सूची तैयार की गई। सूची में शामिल लोगों को वरीयता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया। अगले दिन सुबह छह बजे रेड शुरू हुई। दिल्ली, मुम्बई, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में छापे पड़े। रेड में 500 पुलिस वाले शामिल हुए और एक साथ 35 जगहों पर छापेमारी की गई। इनमें से कुछ लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ भी हुई। पूछताछ में 25 सवाल पूछे गए। जिसमें शाहीन बाग का प्रदर्शन, दिल्ली में किसान आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की खबरों को लेकर सवाल थे। पत्रकारों से विदेशी दौरे से जुड़े सवाल भी पूछे गए। शाम तक फिर उन्हें घर जाने दिया गया। इसके साथ डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों को जांच के लिए जब्त और एकत्रित किया गया है।

न्यूजक्लिक की स्थापना प्रबीर पुरकायस्थ ने 2009 में की थी। इसके एडिटर इन चीफ पुरकायस्थ ही हैं। लेफ्ट इकोसिस्टम के पत्रकार और कर्मचारी इस वेबसाइट की यूएसपी हैं। लेफ्ट दलों का चीन प्रेम कोई छुपी हुई बात नहीं है। वेबसाइट से कुछ पूर्व टीवी पत्रकार भी जुड़े हैं, जो इन दिनों मुख्यधारा की मीडिया से बाहर आकर यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मोदी को भला बुरा कहने को पत्रकारिता कहते हैं। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ही अमेरिकी अखबार न्यूयार्क टाइम्स ने एक खुलासे में दावा किया था कि न्यूजक्लिक उस वैश्विक नेटवर्क में शामिल है, जिसमें अमेरिका के अरबपति नेविल रॉय सिंघम से फंड मिलता है और नेविल रॉय सिंघम का संबंध चीनी कंपनियों से है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित खबर के बाद 17 अगस्त को न्यूजक्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद निरोधक कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया। एनवाईटी की रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि न्यूजक्लिक नाम की वेबसाइट को चीन के प्रोपगेंडा को चलाने के लिए पैसा मिल रहा है।

अभी कुछ दिनों पहले 28 सितम्बर को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ग्लोबल इंगेजमेंट सेंटर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक है, %हाउ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सीक टु रिसेप द ग्लोगल इन्फोरमेशन एन्वायरमेंट।% रिपोर्ट को पढ़कर यह बात स्पष्ट होती है कि चीन सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में मीडिया को अपने पक्ष में प्रभावित करना चाहता है। इसके लिए उसने सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। वह इस दिशा में निवेश भी कर रहा है। वह अपने यहां चाहे सूचनाओं को हर स्तर पर प्रतिबंधित कर रहा हो लेकिन उसे दुनिया भर की सूचनाएं अपने पक्ष में चाहिए।

इसके लिए चीन की मीडिया और उसके सीक्रेट एजेन्ट दुनिया भर में ऐसे मीडिया समूहों अथवा पत्रकारों की पहचान करते हैं जो पैसा लेकर नैरेटिव से लेकर महत्वपूर्ण सूचनाओं को उन तक पहुंचाने में मदद करे। अधिक पुरानी बात नहीं है, जब चीनी एप्लीकेशन यूसी न्यूज ब्राउजर वामपंथी इको सिस्टम के पत्रकारों की आमदनी का मुख्य जरिया था। आजकल यूट्यूब चैनल चलाने वाले कई पत्रकार उन दिनों यूसी के लिए खबर लिख रहे थे। उन्होंने लाखों रुपए यूसी से कमाए लेकिन भारत की सुरक्षा एजेन्सियों के लिए वह एप एक सिरदर्द बन गया था। उस एप के माध्यम से भारत की बहुत सी संवेदनशील सूचनाएं और ढेर सारा डाटा चीन जा रहा था। प्रेस क्लब आफ इंडिया के परिसर में लंबे समय तक यूसी न्यूज का विज्ञापन लगा रहा था। बाद में भारत सरकार ने यूसी न्यूज समेत 58 अन्य चीनी एप को प्रतिबंधित किया।

उसी दौरान राजीव किष्किन्धा नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक यू ट्यूबर राजीव शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। राजीव शर्मा चीन सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले %ग्लोगल टाइम्स% के लिए साप्ताहिक स्तम्भ लिखता था। चीन का एक खुफिया एजेंट लिंक्ड-इन के माध्यम से उससे जुड़ा। राजीव को अपने खर्चे पर उसने चीन बुलाया। उसके बाद वह लगातार राजीव के संपर्क में रहा। राजीव के माध्यम से उस एजेंट ने बहुत सारी खुफिया जानकारी निकलवाई। पैसे के लिए राजीव सब करता रहा। यह सब कितने दिन चलता, आखिर राजीव शर्मा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी स्पेशल सेल ने की। अब उसकी जमानत हो गई है। राजीव चीनी एजेन्ट के लिए अब किसी काम का नहीं रहा। उसकी पहचान हो गई थी। इसलिए राजीव नहीं तो न्यूजक्लिक ही सही। बहरहाल न्यूजक्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उन्हें न्यूजक्लिक को चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों का कोर्ट में जवाब देना है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-9)

गतांक से आगे...

अहंकार ही समस्त विपत्तियों के आगमन का सेतु है। इसी से मनोविकार उत्पन्न होते हैं और तरह-तरह की इच्छा-आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव होता है। इस कारण मनुष्य का अहंकार से बढ़कर और कोई भी शत्रु नहीं है। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने चराचर रूप जिन-जिन भोगों का उपभोग किया है, वे सभी मिथ्या, भ्रमरूप थे। अहंकार का शून्य होना ही जीवन की यथार्थता है। वस्तु तो मात्र अहंकार शून्यता ही है। यह मन व्यर्थ ही परेशान होकर यत्र-तत्र दौड़ता रहता है।

व्यर्थ ही दूर-दूर तक भ्रमण करता रहता है। इसका स्वभाव गाँव में इधर-उधर घूमने वाले कुत्ते की तरह है। मैं भी तृष्णारूपी कुतिया के पीछे-पीछे कुत्ते की भाँति भटकता हुआ इस प्रकार क्रूर मन के वशीभूत होकर जड़वत् हो गया था। हे ब्रह्मन्! अब मैं उसके प्रभाव से पूर्णरूपेण मुक्त हो गया हूँ। हे ब्रह्मन्! चित्त को नियंत्रित करना, समुद्र को पूरी तरह पीने से भी कठिन है, सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकने से भी कठिन है और अग्नि के भक्षण से भी कठिन है। यह चित्त बाह्य एवं अन्त:करण में विषय भोगों को ग्रहण करने वाला है, उसके आधार पर ही जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाओं से युक्त संसार की स्थिति निर्भर है। चित्त के नष्ट होने पर यह जगत् नष्ट हो जाता है। अत: प्रयासपूर्वक चित्त की ही चिकित्सा करनी चाहिए।

हे श्रेष्ठ मुने! मैं जिन श्रेष्ठ सद्गुणों का आश्रय प्राप्त करता हूँ, मेरी तृष्णा उन श्रेष्ठ गुणों को ठीक वैसे ही काट देती है, जैसे कि दुष्ट मूषिका (चुहिया) वीणा के तारों को काट देती है। यह तृष्णा चञ्चल बंदरिया के समान है, जो न लाँघने योग्य स्थान पर भी अपना पैर टिकाना चाहती है। वह तृप्त होने पर भी भिन्न-भिन्न फलों की इच्छा करती रहती है।

एक जगह पर लम्बे समय तक नहीं रुकती क्षणमात्र में ही वह आकाश एवं पाताल की सैर कर डालती है, क्षण मात्र में ही दिशारूपी कुञ्जों में भ्रमण करने लगती है। यह तृष्णा हृदय कमल में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। यह तृष्णा ही इस नश्वर जगत् के समस्त दु:खों में दीर्घ काल तक दु:ख देने वाली है, जो अन्त:पुर में निवास करने वालों को भी महान् संकट में डाल देती है। यह तृष्णा एक महामारी-हैजा है। इसे वही श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट कर सकता है, जिसने चिन्ता का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। यदि चिन्ता का थोड़ा भी परित्याग कर दिया जाए, तो अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि थोड़ी-सी भी चिन्ता मन में शेष रही, तो उससे असीम दु:ख की प्राप्ति होती है।

देह के सदृश तुच्छ, गुणरहित तथा शोक करने योग्य अन्य दूसरा कोई नहीं। इस शरीर रूपी विशाल गृह में अहंकाररूपी गृहस्थ निवास करता है। यह शरीर चाहे दीर्घकाल तक रहे अथवा शीघ्र ही नष्ट हो जाए, उसकी मुझे किञ्चित् मात्र भी चिन्ता नहीं है।

क्रमश: ...

पराक्रमी व प्रसन्नचित व्यक्तित्व के धनी थे गुरु गोविन्द सिंह

ललित गर्ग

भारत की रत्नगर्भा माटी में संतपुरुषों, गुरुओं एवं महामनीषियों की श्रृंखला में एक महापुरुष हैं गुरु गोविन्द सिंह। जिनकी दुनिया के महान तपस्वी, महान कवि, महान योद्धा, महान संत सिपाही साहिब आदि स्वरूपों में पहचान होती है। जिन्होंने कर्तृत्ववाद का संदेश देकर औरों के भरोसे जीने वालों को स्वयं महल की नींव खोद ऊंचाई देने की बात सिखाई। भाग्य की रेखाएं स्वयं निर्मित करने की जागृत प्रेरणा दी।

गुरु गोविन्द सिंह बचपन से ही बहुत पराक्रमी व प्रसन्नचित व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें सिपाहियों का खेल खेलना बहुत पसंद था। बालक गोविन्द बचपन में ही जितने बुद्धिमान थे उतने ही अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी लोहा लेने में पीछे नहीं हटते थे। वे एक कुशल संगठक थे। दूर-दूर तक फैले हुए सिख समुदाय को 'हुक्मनामे' भेजकर, उनसे धन और अस्त्र-शस्त्र का संग्रह उन्होंने किया था। एक छोटी-सी सेना एकत्र की और युद्ध नीति में उन्हें कुशल बनाया। उन्होंने सुदूर प्रदेशों से आये कवियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। यद्यपि उन्हें बचपन में अपने पिता श्री गुरु तेगबहादुरजी से दूर ही रहना पड़ा था, तथापि तेगबहादुरजी ने उनकी शिक्षा का सुव्यवस्थित प्रबंध किया था। साहेबचंद खत्रीजी से उन्होंने संस्कृत एवं हिन्दी भाषा सीखी और काजी पीर मुहम्मदजी से उन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा ली। कश्मीरी पंडित कृपारामजी ने उन्हें संस्कृत भाषा तथा गुरुमुखी लिपि में लेखन, इतिहास आदि विषयों के ज्ञान के साथ उन्हें तलवार, बंदूक तथा अन्य शस्त्र चलाने व घुड़सवारी की भी शिक्षा दी थी। श्री गोविन्द सिंहजी के हस्ताक्षर अत्यंत सुन्दर थे। वे चित्रकला में पारंगत थे। सिराद-एक प्रकार का तंतुवाद्य, मृदंग और छोटा तबला बजाने में वे अत्यंत कुशल थे। उनके काव्य में ध्वनि नाद और ताल का सुंदर संगम हुआ है। इस तरह गुरु गोविन्द सिंह कला, संगीत, संस्कृति एवं साहित्यप्रेमी थे।

निर्भीकता, साहस एवं तत्परता के गुणों से युक्त श्री गुरु गोविन्द सिंहजी का जन्म संवत् 1723 विक्रम की पौष सुदी सप्तमी अर्थात 22 दिसम्बर सन् 1666 में हुआ। बालक गोविन्द सिंह के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष पटना में ही बीते। अपने पिता के बलिदान के समय गुरु गोविन्द सिंह की आयु मात्र 9 वर्ष की थी। इतने कम उम्र में गुरु पद पर आसीन होकर उन्होंने गुरु पद को अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से और भी गौरवान्वित किया। शासक होकर भी उनकी नजर में सत्ता से ऊंचा समाज एवं मानवता का हित सर्वोपरि था। यूं लगता है वे जीवन-दर्शन के पुरोधा बन कर आए थे। उनका अथ से इति तक का पुरा सफर पुरुषार्थ एवं शौर्य की प्रेरणा है। वे सम्राट भी थे और संन्यासी भी। आज उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व और कर्तृत्व सिख इतिहास का एक अमिट आलेख बन चुका है। उन्हें हम तमस से ज्योति की ओर एक यात्रा एवं मानवता के अभ्युदय के सूर्योदय के रूप में देखते हैं।

07 अक्टूबर 1708 में गुरू गोविन्द सिंह जी को नांदेड साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गये। गुरु गोबिंद सिंहजी एक साहसी योद्धा के साथ-साथ एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने बेअंत वाणी के नाम से एक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना करने का गोविन्दसिंहजी का मुख्य उद्देश्य पंडितों, योगियों तथा संतों के मन को एकाग्र करना था। इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुरजी ने तथा इन्होंने मुगल शासकों के विरुद्ध काफी युद्ध लड़े थे। जिन युद्धों में इनके पिताजी शहीद हो गये थे। श्री तेगबहादुरजी के शहीद होने के बाद ही सन् 1699 में गुरु गोविन्द सिंहजी को दशवें गुरु का दर्जा दिया गया था। गुरु गोविन्द सिंहजी ने युद्ध लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य ककार धारण करने की घोषणा भी की थी। सिख धर्म के ये पांच क-कार हैं- केश, कडा, कंघा, कच्छा और कटार। ये शौर्य, शुचिता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के संकल्प के प्रतीक है।

मालदीव से संदेश : आसान नहीं है चीन से निकटता

महेंद्र वेद

एक समय था, जब भारत कहता था और सभी गणमान्य नेता बिना कुछ किए इस बात से सहमत होते थे कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति होनी चाहिए। पिछली शताब्दी के शीतयुद्ध काल के नारे और भावनाओं ने बढ़ती भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया, जिसमें अन्य शक्तिशाली देश गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस क्षेत्र के तीन देशों-नेपाल, श्रीलंका और मालदीव ने हाल के वर्षों में या तो भारत समर्थक या चीन समर्थक सरकारें चुनी हैं। बीते रविवार यानी एक अक्तूबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है, जो घोषित रूप से चीन समर्थक है। मोहम्मद मुइज ने 54 फीसदी से अधिक वोट पाकर इब्राहिम सोलिह को निर्णायक रूप से हरा दिया। वर्ष 2008 के बाद से वहां कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव नहीं जीत सका है। चुनाव जीतने के बाद मुइज ने इस नतीजे को %मालदीव की स्वतंत्रता वापस पाने के लिए एक मजबूत निर्णय बताया। संदेश यह है कि हर चुनाव के साथ स्वतंत्रता आती-जाती रहती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। पांच साल पहले जब सोलिह जीते थे, तो उनके पूर्ववर्ती चीन-समर्थक अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 वर्ष की जेल की सजा हुई थी। मुइज चाहते हैं कि सोलिह यामीन को 17 नवंबर को होने वाले सत्ता हस्तांतरण से पहले जेल से निकाल दें और उन्हें नजरबंद कर दें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुइज को बधाई दी और सहायता व परियोजनाओं समेत संबंधों को

जारी रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। लेकिन मालदीव की राजधानी माले से आने वाली सभी खबरें बताती हैं कि यह परिवर्तन भारत से हिंद महासागर द्वीपसमूह के लिए चीन समर्थक बदलाव की शुरुआत कर सकता है। मुइज के प्रोग्रेसिव एलायंस गठबंधन ने अतीत में खुलेआम चीन के साथ संबंधों का समर्थन किया है। इससे सोलिह के कार्यकाल के दौरान की इंडिया फर्स्ट नीति समाप्त हो जाएगी, जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं। चुनाव जीतते ही मुइज ने कहा है कि वह अपने चुनावी वादे पर डटे हुए हैं और भारतीय सेना को मालदीव के द्वीपसमूह से हटाएंगे। पारंपरिक रूप से मालदीव भारत के प्रभाव में रहा है। लेकिन नई दिल्ली और बीजिंग, दोनों ने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए मालदीव को लाखों डॉलर ऋण और अनुदान के रूप में दिए हैं।

दोनों सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मालदीव में अपनी उपस्थिति मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यस्त रहने वाले पूर्व-पश्चिम शिपिंग लेन तक फैला है। अपनी तेजी से बढ़ती नौसेना के साथ चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान तक अपनी पहुंच बनाना चाहेगा, जिसे भारत रोकना चाहता है। बीजिंग खाड़ी से अपनी ऊर्जा आपूर्ति की भी रक्षा करना चाहेगा, जो उसी मार्ग से होकर गुजरती है। यह मालदीव में %आयाराम-गयाराम% की स्थिति को बतलाता है। पश्चिमी जगत चाहेगा कि भारत वहां टिका रहे और रणनीतिक कारणों से अपने प्रभाव का विस्तार करे। इसके अलावा, मालदीव एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है। पर अब हर कोई सरकार में बदलावों के साथ-साथ राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं से सहमत दिखता है।

मालदीव में भारत-चीन कारक हावी है। पिछले दशक में नई दिल्ली ने मालदीव को दो हेलिकॉप्टर और एक छोटा विमान दिया था। वर्ष 2021 में मालदीव के रक्षा बल ने कहा कि भारतीय विमानों के संचालन और रख-रखाव के लिए लगभग 75 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में थे। उसके तुरंत बाद विपक्ष ने %इंडिया आउट% अभियान शुरू किया, जिसमें मांग की गई कि भारतीय सुरक्षाकर्मी मालदीव से चले जाएं। विपक्ष ने भारत के साथ सोलिह के संबंधों पर लगातार ध्यान केंद्रित किया, खासकर मालदीव में भारतीय सुरक्षाकर्मियों की कथित तैनाती पर। लेकिन मालदीव सरकार ने उस द्वीपीय राष्ट्र में किसी भी तरह की भारतीय सैन्य गतिविधि को खारिज कर दिया। मतदान से ठीक एक दिन पहले विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इन्हीं चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर और डोर्नियर हवाई जहाजों को संचालित करने के लिए लाए गए भारतीय सैनिकों की संख्या में यामीन सरकार के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और पासा भारत के खिलाफ तथा चीन के पक्ष में चला गया। नवीनतम परिवर्तन का मतलब यह हो सकता है कि प्रमुख भारतीय परियोजनाओं का भविष्य भी अधर में लटक सकता है। वर्ष 2012 के तख्तापलट में नाशीद के अपदस्थ होने के बाद यामीन शासन ने माले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और संचालन के लिए भारतीय कंपनी जीएमआर समूह के साथ किए अनुबंध को एकतरफा खत्म कर दिया। जीएमआर समूह ने बाद में मालदीव सरकार से मुआवजा पाने का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया। उसके बाद बड़ी चीनी कंपनियां मालदीव आईं और प्रमुख बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। लेकिन चीन की तरफ मालदीव का वापस लौटना आसान नहीं होगा, बल्कि मालदीव चीन के गहरे कर्ज में डूब जाएगा। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और अब संसद के स्पीकर मोहम्मद नाशीद कहते हैं कि चीनी कर्ज 3.1 अरब डॉलर का है। इसमें सरकार से सरकार को ऋण, राज्य उद्यमों को दिया गया ऋण और मालदीव सरकार की गारंटी पर निजी क्षेत्र को दिया गया ऋण शामिल है।

हालांकि इस आंकड़े पर विवाद है। मालदीव के कुछ अधिकारियों और चीनी प्रतिनिधियों का अनुमान है कि माले पर चीन का बकाया 1.1 अरब डॉलर से 1.4 अरब डॉलर के बीच है, जो इस द्वीपीय देश के लिए तब भी बड़ी रकम है। । जीडीपी करीब 4.9 अरब डॉलर है। यदि नाशीद के आंकड़ों को मानें, तो ऋण देश के वार्षिक जीडीपी के आधे से अधिक है।

हिन्द स्वराज्य

गोला-बारूद (भाग-6)

गतांक से आगे...

हम आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। इस बल को चाहे दयाबल कहें, चाहे आत्मबल कहें या सत्याग्रह कहें। यह बल अविनाशी है और इस बल का उपयोग करने वाला अपनी हालत को बराबर समझता है। इसका समावेश हमारे बुजुर्गों ने एक नहीं सब रोगों की दवा में किया है। यह बल जिसमे है उसका हथियार बल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा अगर आग में पैर रखे, तो उसको दबाने की मिसाल की छानबीन करने में तो आप हार जायेंगे। बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? मान लीजिये कि बच्चा ऐसा जोर करे कि आपको मारकर वह आग में जा पड़े। तब तो आग में पड़े बिना वह रहेगा ही नहीं। इसका उपाय आपके पास यह है- या तो आग में पड़ने से रोकने के लिए आप उसके प्राण ले लें, या उसका आग में पड़ना आपसे देखा नहीं जाता इसलिए आप स्वयं आग में पड़कर अपनी जान दे दें। आप बच्चे के प्राण तो नहीं ही लेंगे। आपमें अगर संपूर्ण दयाभाव न हो, तो मुमकिन है कि आप अपने प्राण नहीं देंगे। तो फिर लाचारी से आप बच्चे को आग में कूदने देंगे। इस तरह आप बच्चे पर हथियार बल का उपयोग नहीं करते हैं। बच्चे को आप और किसी तरह रोक सकें तो रोकेंगे; और वह बल कम दर्जे का, लेकिन हथियार बल ही होगा ऐसा भी आप न समझ लें। वह बल और ही प्रकार का है। उसी को समझ लेना है। बच्चे को रोकने में आप सिर्फ बच्चे का स्वार्थ देखते हैं। जिसके ऊपर आप अंकुश रखना चाहते हैं, उस पर उसके स्वार्थ के लिए ही अंकुश रखेंगे। यह मिसाल अंग्रेजों पर जरा भी लागू नहीं होती। आप अंग्रेजों पर जो हथियार बल का उपयोग करना चाहते हैं उसमें आप अपना ही यानी प्रजा का स्वार्थ देखते हैं। उसमें दया जरा भी नहीं है। अगर आप यों कहें कि अंग्रेज जो अधम-नीच काम करते हैं वह आग है, वे आग में अज्ञान के कारण जाते हैं और आप दया से अज्ञानी को यानी बच्चे को उससे बचाना चाहते है, तो इस प्रयोग को आजमाने के लिए आपको जहाँ-जहाँ जो भी आदमी नीच काम करता होगा वहाँ-वहाँ पहुँचना होगा और सामने वाले के—बच्चे के-प्राण लेने के बजाय अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। इतना पुरुषार्थ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। पर यह बात बिलकुल असंभव है।

जाति जनगणना से लोकसभा चुनावों पर क्या होगा असर ?

जयसिंह रावत

बिहार की नीतीश कुमार सरकार द्वारा जारी किए गए जातीय गणना के आंकड़ों ने फिलहाल देश में हलचल तो मचा ही दी है। कारण साफ है। देश का सामाजिक तानाबाना लगभग एक जैसा है और समाज के साथ ही शासन प्रशासन में अगड़ी जातियों का वर्चस्व जगजाहिर है। यही अगड़ा वर्ग देश की राजनीति को भी दिशा देता है। बिहार की गणना में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ों को मिलाकर उनका कुल योग 63.13 प्रतिशत हो रहा है और उनके साथ अगर मुसलमानों की 17.7 प्रतिशत आबादी मिला दी जाए तो वह 80.83 प्रतिशत हो जाती है। पहले सपा और राजद जैसे कुछ दल ही जातीय आधार पर जनगणना के पक्षधर माने जाते थे, लेकिन इंडिया के बैनर तले समूचा विपक्ष जातीय गणना के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि भाजपा के हिन्दुत्व के ब्रह्मास्त्र के आगे विपक्ष के पास यही एक अमोघ शस्त्र बचा था जो उसने तरकश से निकाल लिया। अब पक्ष और विपक्ष की तैयारियों से साफ जाहिर है कि 2024 का चुनाव देश के सामने खड़ी ज्वलंत चुनौतियों और जनता की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं को लेकर नहीं बल्कि धर्म और जातियों के नाम पर लड़ा जाएगा।

बिहार सरकार द्वारा विवादित जातीय गणना के नतीजे सार्वजनिक किए जाने के बाद अब कर्नाटक की सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की बारी है। कर्नाटक में एच. कंथाराज के नेतृत्व में आयोग ने 2015-16 में सर्वेक्षण किया था। सिद्धारमैया पर सबसे अधिक अपनी ही पार्टी का दबाव होगा, क्योंकि जातीय गणना को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सबसे अधिक मुखर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कर्नाटक में दो प्रमुख जातीय समुह लिंगायत- वीरशैव और वोक्कालिंगा हैं, जिनकी जनसंख्या क्रमश: 14 और 11 प्रतिशत बताई जाती है। लेकिन ये दोनों ही जातीय गणना के विरोध में हैं। दोनों समुदायों का दावा है कि उनकी संख्या रिपोर्ट में लीक हुए आंकड़ों से कहीं अधिक है। अगर कर्नाटक ने भी आंकड़े सार्वजनिक कर दिए तो फिर मोदी सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा।

यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं के दबाव में 2011 में ''सोशियो-इकनॉमिक

कास्ट सेंसस'' कराने का फैसला लिया था। यह गणना 2013 में पूरी भी हो गई थी। इसके जरिए जुटाए गए डाटा के आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होनी थी, मगर 2014 में सरकार बदल गई। फिर 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जल्द ही जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाएगा जो कि अब तक नहीं हुए। इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने की कोई संभावना भी नहीं है। कारण विपक्ष के इस दांव से भाजपा के हिन्दू वोट बैंक के बिखरने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

धर्म की ही तरह जाति भी हिन्दू समाज की सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि फोटो खिंचाने के लिए चाहे आप किसी दलित के घर खाना खाने चले जाएं मगर उस दलित से बेटी का रिश्ता शायद ही करना चाहें। जातियां व्यक्ति विशेष की पहचान भी होती हैं इसलिए लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति का भी उल्लेख करते हैं। इसके साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि समाज में कुछ जातियां वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर बहुत पिछड़ी रह गईं। आजादी के बाद भी तरक्की के अवसर मुट्ठीभर अगड़ी जातियों ने लपक लिए। यहां तक कि पिछड़ी जातियों में भी जो अगड़ी जातियां थीं उन्होंने तरक्की के अवसरों को अत्यन्त पिछड़े लोगों तक पहुंचने से पहले हथिया लिया। इसका जीता-जागता उदाहरण हमारे सामने कुछ जनजातियां हैं जिनकी शासन-प्रशासन तक पहुंच हो गई जबकि अण्डमान निकोबार की जातियों तक प्रगति के अवसरों पहुंचना तो रहा दूर उनका अपना अस्तित्व ही गंभीर खतरे में है, इसलिए समाज की अंतिम पक्तियों पर बैठे लोगों की बात करना या उनकी व्यथा कथा को आवाज देना हर भारतीय का कर्तव्य है। कोई भी इंसान जाति या धर्म का टैग लगाकर पैदा नहीं होता है। मनुष्य के पैदा होने के बाद उस पर हिन्दू-मुसलमान या अगड़ी-पिछड़ी जाति का लेबल लगाया जाता है। प्राचीन काल में भी जातियां कर्म के अनुसार तय होती थी। यहां तक कि सनातन धर्मावलम्बियों के अनुसार मानव जाति के पहले संविधान और धर्मशास्त्र ''मनुस्मृति'' में मनुष्यों के जिन चार वर्णो का उल्लेख है उनका वर्गीकरण उनके कर्म के आधार पर किया गया है। (हालांकि लोग विभेदकारी उस मनुवादी वर्ण व्यवस्था की मुखालफत करने लगे हैं) चूंकि पैतृक व्यवसाय अपनाना भी एक परम्परा रही है और उसके लिए लोगों को वैसे ही दीक्षा और संस्कार मिलते रहे हैं, इसलिए पुश्तैनी व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे।

अब व्यवसाय में बदलाव तो आ रहा है मगर पुरखों से विरासत में मिली जातियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। चूंकि तब समाज और राजे महाराजाओं की शासन व्यवस्था जातियों के आधार पर चलती थी। कोई जाति रक्षा की जिम्मेदार थी तो कोई कोष की और कोई प्रशासन की जैसी अन्य जिम्मेदारियां संभालती थी। लेकिन आज संविधान ही शासन प्रशासन चलाता है। हां ! आज भी कुछ लोग जाति के आधार पर कार्य कर रहे हैं अन्यथा जातियों के आधार पर कर्म का निर्धारण का प्राचीन सिद्धान्त लगभग निरर्थक हो चुका है।

इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में गैरकानूनी कार्यों को छोड़कर सबके लिए कोई भी कार्य करने की छूट है। यह सही है कि समाज में बहुत सारे मानव समूह जिन्हें आप जातियां या उपजातियां कह सकते हैं, अब भी संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने का फल नहीं चख पा रही हैं, इसलिए जब तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी इन जातियों की पहचान नहीं होगी तब तक उन्हें मुख्य धारा तक लाने के प्रयास कामयाब नहीं होंगे। पिछड़ी जातियों में भी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ी नहीं रह गई उन्हें हटाए बिना अत्यधिक पिछड़ो का भला नहीं हो सकता। जातीय गणना से जुड़े सामाजिक बदलाव वाले दूसरे पहलू पर भी चर्चा की जानी चाहिए जो कि नहीं हो रही है, जिस 1931 की अंतिम जातीय गणना का बार-बार उल्लेख हो रहा है उसमें स्वयं इस तरह की गणना की सटीकता और प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए हैं, शायद इसीलिए 1931 के बाद अंग्रेजों ने भी जातीय गणना कराने की जरूरत नहीं समझी। जॉन हेनरी हट्टन के नेतृत्व में कराई गई उस जनगणना रिपोर्ट के वॉल्यूम-एक भाग-एक के पैरा 182 से आगे जातीय गणना पर कई संशय उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ प्रदेशों में एक जाति स्वयं को ब्राह्मण दर्ज कराती है तो दूसरे राज्य में उसी नाम की जाति स्वयं का राजपूत बताती है। यही नहीं 1921 की जनगणना में कुछ जातियों ने स्वयं को राजपूत बताया था, लेकिन 1931 में उन्होंने स्वयं का ब्राह्मण दर्ज कराया है।

सन् 1931 की जनगणना में जातीय ग्रुपिंग का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि चार वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया इसलिए कुछ जातियों ने स्वयं को ब्राह्मण बताना शुरू किया। इसी तरह दूसरे क्रम की क्षत्रिय जाति में तीसरे क्रम की और चौथे क्रम की जातियां शामिल होने लगी। रिपोर्ट में संयुक्त प्रान्त की एक अनुसूचित जाति के लोगों का उल्लेख भी किया गया है जिसने स्वयं को सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी राजपूत के तौर जनगणना में दर्ज कराया है। दरअसल, आज समाज में जिस तेजी से बदलाव आ रहे हैं उसी तेजी से जातियों का आपस में संविलयन भी हो रहा है। लव जेहाद रटने वाले चाहे जो बोलें, मगर अब युवावर्ग वर्ण व्यवस्था और मजहबी सीमाओं को लांघ कर बेधड़क मनचाही लडक़ी या लड़के से विवाह कर रहे हैं। यह एक सामाजिक समरसता के लि, जरूरी प्रक्रियाभी है। सवर्णों की पिछड़ी जातियां भी अगड़ी जातियों के समूह में विलीन होती जा रही हैं। इसलिए सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों में पिछ़ड़ी जातियों का चिन्हीकरण उतना आसान नही होगा।

वोटों के लिए धर्म के आधार पर समाज को बांटने कर नतीजा हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब जातियों के नाम पर सामाजिक बंटवारे की नौबत मुंहबाए खड़ी हो गई है। नब्बे के दशक में मंडल आयोग विरोधी आन्दोलन में कम से कम 159 युवाओं ने आत्महत्या की कोशिश की थी और राजीव गोस्वामी समेत 63 युवाओं ने आत्मदाह जैसे तरीकों से विरोध प्रकट करने के लिए आत्महत्या कर ली थीं।

चुनावों को लेकर भाजपा की नई रणनीति

जलज मिश्रा

बिहार के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना की मांग के साथ ओबीसी मुद्दों को केंद्र में लाने की विपक्ष की रणनीति को धराशाई करने के लिए सरकार बड़ी तैयारी में है। विपक्षी हमले की धार कुंद करने के लिए सरकार में जहां एक बार फिर से समान नागरिक संहिता पर मंथन का दौर शुरू हुआ है, वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ओबीसी क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सरकार के सूत्र ने कहा कि योजना मोदी सरकार के बीते नौ साल में ओबीसी के हक में लिए गए फैसलों का आक्रामक प्रचार करने के साथ इस वर्ग से जुड़ी दूसरी अहम मांगों को पूरी करने का है। इस क्रम में बीते करीब तीन साल से लंबित क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाने का फैसला जल्द लिया जा सकता है। सरकार उन लंबित मांगों का भी अध्ययन कर रही है, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। भाजपा की योजना जुलाई महीने में ही उत्तराखंड के जरिए यूसीसी लागू करने की शुरुआत करने की थी। हालांकि इस बीच आदिवासी समुदाय की आपत्तियों और मणिपुर में कुकी बनाम मैतई जातीय हिंसा के कारण सरकार ने अपने पांव पीछे खींच लिए। अब यूसीसी पर नए सिरे से मंथन शुरू हुआ है। बीते बुधवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की गृह मंत्री अमित शाह से लंबी चर्चा हुई है। इसे यूसीसी की ओर नए सिर से कदम बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। क्रीमीलेयर से जुड़े नए प्रस्ताव में विवाद का कारण बने कृषि संबंधी आय को दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार की योजना क्रीमीलेयर के दायरे को आठ लाख से बढ़ा कर कम से कम 12 लाख रुपये करने की है। क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाने का मामला 2021 से अटका हुआ है। भाजपा और मोदी सरकार बीते नौ साल में ओबीसी के हक में लिए गए निर्णयों का आक्रामक प्रचार के लिए व्यापक अभियान छेड़ेगी। इसके तहत देश भर में ओबीसी सम्मेलन किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में मोदी सरकार द्वारा ओबीसी आयोग को दिए गए सांविधानिक दर्जा, नीट में ओबीसी कोटा, ओबीसी छात्रों को फैलोशिप, पहली बार ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना, नवोदय, सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर भर्ती में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करने संबंधी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। सरकार यह भी बताएगी की केंद्रीय योजनाओं के कारण ओबीसी को कितना लाभ पहुंचा।

जाति जनगणना का क्या होगा राजनीतिक परिणाम ?

उमेश चतुर्वेदी

राजनीति के हर कदम के पीछे सोची-समझी रणनीति ही नहीं, सुचिंतित कारण भी होते हैं। यह अकारण नहीं है कि गांधी जयंती के दिन बिहार की नीतीश-तेजस्वी सरकार ने राज्य की जाति जनगणना को जारी किया। गांधीजी जाति की आधुनिक व्यवस्था को खत्म होते देखना चाहते तो थे, लेकिन जातियों के बीच आपसी खींचतान और सिर-फुटौव्वल की कीमत पर नहीं। लेकिन क्या बिहार की जाति गणना के आधुनिक आंकड़ों को इस नजरिए से देखा और परखा जा सकता है? जाति जनगणना के आंकड़ों के जाहिर होने के बाद राज्य और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? जब किसी जाति, समुदाय या समूह को लेकर कोई आंकड़ा आता है, तो नए सिरे से उसे राजनीतिक ताकत और आरक्षण आदि देने की मांग शुरू हो जाती है। इसलिए इसमें कोई दो-राय नहीं कि बिहार के जातीय आंकड़े सामने आने के बाद ऐसी मांग शुरू होगी। जैसे अब तक माना जाता था कि कोइरी और कुशवाहा जाति के लोगों की संख्या कुर्मी समाज की तुलना में कम है। लेकिन नए आंकड़े बताते हैं कि बिहार के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में सबसे ज्यादा यानी 14.2 प्रतिशत वाले यादव समुदाय के बाद कुशवाहा जाति ही है। जिसकी संख्या करीब 4.21 प्रतिशत है। इसी तरह दुसाध या पासवान की संख्या 5.3 प्रतिशत है। इसके बाद नंबर है रविदास या चमार कही जाने वाली जाति का, जो करीब 5.2 प्रतिशत है। अति पिछड़ा समुदाय के जातियों वाले लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत से ज्यादा है। प्रचलित राजनीतिक मानकों पर भी इन जातियों के संदर्भ में राजनीतिक नेतृत्व को देखिए। कांशीराम ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा बेशक दलितवादी राजनीति ने दिया, लेकिन इसे धीरे-धीरे पिछड़ावाद की राजनीति करने वाले समाजवादी खेमे ने अख्तियार कर लिया। अब तो वह कांग्रेस भी यह नारा लगा रही है, जिसने 1984 में नारा दिया था, जात पर न पांत पर, इंदिरा जी की बात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। अगर इस लिहाज से देखें तो बिहार को अगर पिछड़ावादी होना होगा या हिस्सेदारी देनी होगी तो रविदास समुदाय के नेतृत्व को ताकत देना होगा। इसी तरह यह भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में आखिर क्यों पूरी ताकत यादव जाति के पास ही रही। अगर वह छिटकी भी तो कुर्मी समुदाय के नीतीश के पास पहुंच गई। आखिर यह ताकत किसी कुशवाहा या कोइरी समुदाय के नेता के पास क्यों नहीं गई? जाति जनगणना के आंकड़ों के बाद जब हिस्सेदारी का विश्लेषण होगा तो ये सारे सवाल उठेंगे। राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर जब बात होगी तो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र जरूरी होगा। रोहिणी आयोग का नतीजा है कि पिछड़ावाद के आरक्षण में सिर्फ चार ताकतवर जातियों को ही फायदा हुआ है। देर-सेवर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी करने का केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। हो सकता है कि राजनीति के तहत वह इसे जारी भी कर दे। इससे साबित होगा कि रोहिणी आयोग ने पिछड़े समुदाय की जिन दबंग जातियों पर आरक्षण का फायदा उठाने की बात कही है, कुछ वैसी ही स्थिति राजनीति की भी है। इससे आज के पिछड़ावादी राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठेंगे।

भ्रष्टाचार को मुद्दा बना कर भाजपा कहीं कामयाब तो कहीं विफल

अमित शर्मा

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। भाजपा इसे शराब घोटाले की गलत करतूत का स्वाभाविक परिणाम बता रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने इसे विपक्षी दलों पर गलत नीयत से किया गया हमला करार दिया है। हालांकि, भाजपा विपक्षी दलों पर पड़े इस तरह के छापों को हमेशा न्यायिक और कानूनी कार्यवाही का स्वाभाविक अंग बताती रही है। उसका यह भी कहना रहा है कि इनके पीछे उसका कोई हाथ नहीं रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसे सरकार के इशारे पर चुनावों के पहले विपक्ष को कमजोर करने की साजिश करार देते रहे हैं। इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच एक तथ्य यह भी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जिन चुनावों के पहले विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई की है, उनमें से कुछ चुनावों में भाजपा को सफलता तो कुछ में विफलता मिली है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण लोकसभा 2019 का चुनाव था। चुनाव के पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ की गई। कांग्रेस नेताओं ने इसके विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन भी किया और इसे गांधी परिवार की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान कई अन्य दलों के नेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई हुई और उन्होंने भी इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनता ने मोदी के भ्रष्टाचार पर वार के दावे पर ज्यादा भरोसा किया और उसे वोट देकर विजयी बनाया।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई हुई। कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के करीबियों के यहां छापेमारी हुई, और करोड़ों

रुपये की नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। कहा गया था कि यह अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के चुनावी धन स्रोतों को बर्बाद करने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी यही आरोप लगा रही थी कि यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी हार देखकर भाजपा उनके करीबियों पर छापे डलवा रही है लेकिन इसके बाद भी वह अपनी हार नहीं टाल सकेगी। लेकिन चुनावों में भाजपा ऐतिहासिक रूप से यूपी में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही।

इसी प्रकार उत्तराखंड, गुजरात, असम और महाराष्ट्र के अनेक विपक्षी दलों के नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की टीमों ने छापे मारे, और भाजपा को इसका लाभ मिला। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के ये छापे भाजपा की जीत की गारंटी नहीं रहे हैं। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई के बाद भी विपक्षी दल वहां जीतने में सफल साबित हुए हैं।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक विधानसभा के चुनाव रहे हैं। यहां चुनाव के पहले कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और उनसे जुड़े लोगों पर खूब छापेमारी हुई, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में चुनाव के पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस यहां जीत हासिल करने में सफल रही।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर खूब छापेमारी हुई थी। कई जगहों से भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई थी। हालांकि इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि, पूरे विपक्ष के एकजुट हो जाने के बाद भी भाजपा पिछले चुनाव के मुकाबले यहां बड़ी बढ़त हासिल करने में कामयाब रही। इसी तरह 2015 में बिहार और 2020 में दिल्ली में भी भाजपा असफल रही।

राजनीतिक विश्लेषक धीरेंद्र कुमार ने अमर उजाला से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि लंबे राजनीतिक जीवन के बाद भी आज तक उन पर भ्र्ष्टाचार का कोई आरोप चिपका नहीं है। विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद भी आज तक उनकी छवि बेदाग बनी हुई है और लोगों को उन पर भरोसा है।

वहीं, भाजपा के सत्ता में आने के दशकों पहले से विपक्ष के कई दलों पर भ्र्ष्टाचार के गम्भीर आरोप लगते रहे हैं। इन मामलों में कई दलों के शीर्ष नेताओं को अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ा है तो कुछ को जेल भी जाना पड़ा है।

यही कारण है कि जनता मोदी के दावों पर भरोसा करती है। विपक्ष के आरोपों के बाद भी मोदी ने स्वयं कहा है कि भृष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में संजय सिंह प्रकरण के बाद भी यदि इस तरह की कार्रवाई जारी रहे तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 में भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ़ कई ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और एजेंसियाँ जाँच कर रहीं हैं लेकिन भाजपा में शामिल होने पर उनके खिलाफ जिस तरह नरमी बरती जाती है उससे विपक्ष के आरोप को भी बल मिलता है।

लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा मिशन 'डी'

आशीष तिवारी

सियासी रोड मैप तो आने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर चार प्रमुख चुनावी राज्यों में तैयार किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा का जो सियासी रोड मैप और तस्वीर तैयार की जा रही है वह सबसे अलग है। सियासत की इस तस्वीर में सभी राजनीतिक दल बसपा के कोर वोट बैंक के माध्यम से अपनी-अपनी सियासी इबारत लिखने की न सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बल्कि दलितों के लिए बड़ा मंच भी तैयार कर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की सबसे ज्यादा हो रही है कि अखिलेश के पीडीए और कांग्रेस के पासी, जाटव वोट पर निशाना लगाने के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दलित सम्मेलन की तैयारी की है उससे कहीं ऐसा ना हो कि मायावती के कर वोट बैंक में जमकर सेंधमारी हो जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी की सियासत में तैयार किए जा रहे मिशन डी यानी मिशन दलित का बड़ा व्यापक असर आने वाले लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में दलित वोट को जोड़ने की सियासत चल रही है। लेकिन इन सबसे इतर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलित वोट को अपने साथ जोड़ने की राजनीतिक दलों ने सियासी जंग शुरू की है वह बहुत रोचक हो चली है। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शुक्ला कहते हैं कि राज्य में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पीडीए मॉडल से दलितों को साधने की पूरी सियासी बिसात बिछा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाल में हुए उपचुनाव में अपनी जीत का पूरा श्रेय इसी पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को ही दिया था। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीडीए के मुताबिक ही अपने गठबंधन को न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं बल्कि आगे की सियासी राह को भी बढ़ा रहे हैं। पार्टी इसी योजना के मुताबिक आने वाले दिनों में होने वाले सम्मेलनों में दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को न सिर्फ मजबूती के साथ आगे रखा जाएगा बल्कि उनके क्षेत्र और इलाकों में पार्टी के बड़े-बड़े जिम्मेदार नेताओं और पदाधिकारी को भी बृहद स्तर पर भेजने की योजना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जिस पीडीए की बात की है दरअसल समाज में इस तबके के लोगों लोगों के साथ मिलकर देश और प्रदेश के बेहतर निर्माण में आगे बढ़ा जा सकता है।

समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के माध्यम से अपनी सियासी राह बना रही है ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी दलितों को अपने पाले में रखने का एक बड़ा दांव खेला है। हालांकि यह दांव शुरुआती दौर में तो दलितों की एक बिरादरी पासी समुदाय पर फोकस करते हुए किया है लेकिन पार्टी सिर्फ पासी ही नहीं बल्कि जाटव समेत अन्य दलित को अपने साथ जोड़ने का मेगा अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी

कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को निर्देश के मुताबिक व अपने-अपने क्षेत्र और इलाकों में दलित समुदाय के साथ भोज करें और उनको संगठनात्मक स्तर पर जोड़ें। इसके साथ-साथ आगे की रणनीतियों के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी के संग बैठकों का आयोजन करने का निर्देश तो मिला ही है बल्कि आने वाले दिनों में दलितों के बीच में पार्टी के बड़े नेताओं के आयोजन करने की रणनीति बनी है। सियासी जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कयूम कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने बड़े दलित नेताओं के चेहरे को आगे करके इस समाज को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है उससे पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में वह अपने खोए हुए इस महत्वपूर्ण वोट बैंक को अपने साथ जोड़ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि उनकी पार्टी जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी धर्म और जातियों के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती आई है। क्योंकि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को आगे लाना है। इसलिए उन सभी लोगों के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।

उत्तर प्रदेश में दलितों की सियासत को अपने साथ जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी सियासी रणनीति बनाई है। योजना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दलित महासम्मेलन कर समुदाय के लोगों से सीधे तौर पर मुखातिब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की योजना के मुताबिक 15 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 27 अक्टूबर को पूर्वांचल के साथ-साथ बनारस में बड़ा सम्मेलन तय किया गया है। इसके अलावा तय योजना के मुताबिक अवध क्षेत्र में भी दलित महासम्मेलन करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक दो नवंबर को इस क्षेत्र में दलित महासम्मेलन कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अलग-अलग राज्यों में दलितों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के लिए तैयार की गई रणनीतिकारों की टीम के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं की उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले दलित महासम्मेलन में न सिर्फ राज्य की बल्कि केंद्र के बड़े नेता शिरकत करने की तैयारी में है। इसमें गृहमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कुछ बड़ी जगह पर बड़े आयोजनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है जिस तरीके से सभी सियासी दल दलितों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं उससे बहुजन समाज पार्टी को निश्चित तौर पर एक काउंटर और बड़ी रणनीति तो बनानी ही होगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक दलित समुदाय ही रहा है। सीएसजेएम विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के पूर्व प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों की भूमिका पर शोध करने वाले डॉक्टर जगतराम कहते हैं कि अगर मायावती की सियासत को ढंग से देखा जाए तो पता चलता है कि बीते चुनाव में कम हुई सीटों के बाद भी उनके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी नहीं हो सकी है। भले ही मायावती की पार्टी को एक लोकसभा के चुनाव में शून्य पर ही क्यों ना सिमटना पड़ा हो। प्रोफेसर जगत राम का मानना है कि लेकिन जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल खासतौर से सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं के माध्यम से जब दलित समाज को अपनी और जोड़ने की तैयारी करता है तो उसका व्यापक असर भी किसी भी जाति विशेष समुदाय पर पड़ता ही है। ऐसे में यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी का दलितों को अपनी और जोड़ने का अभियान चलाना कारगर नहीं होगा ऐसा सियासत में नहीं सोचना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी बहुत सक्रियता के साथ दलित समाज को अपने साथ नहीं जोड़ती तो संभव है उसका खामियाजा भी दलितों के बटे हुए वोट बैंक के तौर पर उनको देखना पड़े। और इसका सीधा-सीधा असर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के वोट बैंक पर पड़ सकता है।

पितृपक्ष में भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का दान

वरना कभी भी पितृदोष से नहीं मिलेगी मुक्ति

पितृपक्ष में दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में दान करने से व्यक्ति को 100 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन, पितृपक्ष में कुछ चीजों का दान करने की मनाही भी है। भूलकर भी पितृपक्ष में इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। वरना पितृदोष से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में जो व्यक्ति दान आदि के कार्य करता है उसको उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती हैं। लेकिन, पितृपक्ष में दान आदि के कार्य करते हुए कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि, इन चीजों का दान करने से आपको पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष में इन 5 चीजों का दान भूलकर भी न करें।

पितृ पक्ष में तेल का दान न करें

पितृ पक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में तेल का दान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। खासकर के सरसों के तेल का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

पितृ पक्ष में पुराने कपड़े न करें दान

पितृ पक्ष में यदि आप कपड़े दान करना चाहते हैं तो याद रखें की दान में सिर्फ नए कपड़े ही दें। अपने पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में नहीं दें।साथ ही जूते चप्पल भी दान न करें। क्योंकि, इस तरह का दान करने से व्यक्ति पर राहु दोष और पितृदोष लगता है। जिससे आपकी तरक्की में बाधा पैदा हो सकती है।

पितृ पक्ष में बेकार और जूठा भोजन का न करें दान

पितृ पक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न दान महा दान होता है। पितृ पक्ष में यदि आप भोजन का दान करना ही चाहते हैं तो अच्छे भोजन का दान करें और किसी को भी अपना जूठा भोजन तो बिल्कुल भी न दें। पितृ पक्ष में अच्छा और शुद्ध भोजन किसी को करवाने से पितर खुश होते हैं।

पितृपक्ष में लोहे के बर्तन न करें दान

पितृपक्ष में कई लोग बर्तन का दान करते हैं लेकिन, इस बात का ख्याल रखें की आप लोहे के बर्तन का दान न करें। लोहे के बर्तन का दान करने से पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर पितृदोष लग सकता है। इसलिए स्टील के बर्तन का ही दान करें।

पितृपक्ष में काले कपड़ों का दान न करें

पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी दान नहीं देने चाहिए। पितृपक्ष में सफेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए। सफेद रंग के कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं।

पितृपक्ष में यहां पितरों का तर्पण श्राद्ध करना होता है कल्याणकारी

पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर से हो रहा है। पितृपक्ष में लोग अपने घर में श्राद्ध करने के अलावा कुछ तीर्थ स्थानों पर जाकर भी अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। बिहार के बोधगया में पितृपक्ष में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। यहां का महत्व सबसे ज्यादा है और यहां देश भर से लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने आते हैं। आइए आपको बताते हैं कि गया के अलावा और कौन से तीर्थ स्थान है जहां पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है।

पितृपक्ष में अधिकांश लोग अपने घर पर ही ब्राह्मणों को भोजन करवारकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और वहां उनका श्राद्ध करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ तीर्थ स्थानों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहां आकर पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये तीर्थ स्थान।

गया, बिहार

वायु पुराण के साथ गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में गया तीर्थ का महत्व सबसे अधिक माना गया है। श्राद्ध कर्म करने के लिए यह स्थान सबसे पवित्र माना गया हे। पुराणों में यह स्थान मोक्ष की भूमि और मोक्ष स्थली कही जाती है। कहते हैं यहां आकर पितरों का श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान यहां हर साल मेला लगता है। इसे पितृ पक्ष मेला कहा जाता है।

ब्रह्मकपाल, बदरीनाथ उत्तराखंड

बदरीनाथ में स्थित ब्रह्मकपाल घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां किया गया पिंडदान गया से भी 8 गुना अधिक फलदायी है। कहते हैं यहां आकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनके आत्मा को तत्काल मुक्ति मिलती है। यहां भगवान शिव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यह स्थान बदरीनाथ धाम से कुछ ही कदम की दूरी पर अलकनंदा के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहां पांडवों ने भी महाभारत युद्ध में मारे गये परिजनों की मुक्ति के लिए पिंडदान किया था।

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पितरों का तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। इलाहाबाद में पितृपक्ष का बहुत बड़ा मेला लगता है। यहां पर दूर-दराज से लोग आकर पिंडदान करते हैं और पितरों के मोक्ष के लिए कामना करते हैं।

हरिद्वार, उत्तराखंड

उत्तराखंड के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक हरिद्वार जहां लोग अपने पूर्वजों के अस्थि विजर्सन के लिए जाते हैं, यहां पर श्राद्ध करने से भी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यहां गंगा नदी स्नान करने से जहां सारे पाप धुल जाते हैं तो वहीं पितरों के नाम का पिंडदान करने से उनकी आत्मा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है।

अयोध्या, उत्तर प्रदेश

भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सरयू नदी के तट पर पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। यहां सरयू नदी के किनारे स्थित भात कुंड पर हर साल कर्म कांड का आयोजन होता है। यहां आकर पहले लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं।

मथुरा, उत्तर प्रदेश

भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुनाजी के तट पर भी हर साल लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। यहां पर वायुतीर्थ में पिंडदान किया जाता है। इसके अलवा विश्रनी तीर्थ और बोधिनी तीर्थ में भी पिंडदान करने लोग जाते हैं। मान्यता है कि यहां चावल और आटे का पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है।

पुष्कर, राजस्थान

राजस्थान का धार्मिक स्थल पुष्कर भी श्राद्ध कर्म के लिए जाना जाता है। यहां पर ब्रह्माजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहां की पवित्र झील के बारे में यह पौराणिक मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। यहां पर 52 घाट हैं जहां पर हर साल पिंडदान करने लोग दूर-दूर से आते हैं।

उज्जैन, मध्य प्रदेश

महाकाल की नगरी उज्जैन में बहती शिप्रा नदी का उद्गम भगवान विष्णु के शरीर से हुआ है। यहां बने घाटों पर हर साल श्राद्ध कर्म करने वालों की भारी भीड़ देखी जाती है। महाकाल की नगरी में श्राद्ध करने से पितृ पूर्ण तृप्त होते हैं।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

भगवान शिव की नगरी काशी में पितरों का श्राद्ध करना परम पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं कि काशी में प्राण त्यागने वाले को यमलोक नहीं जाना पड़ता है। वैसे ही यहां पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर गंगा नदी के तट पर कर्मकांड होते हैं।

ऑफिस हो या घर वास्तु के इन नियमों का रखें ख्याल

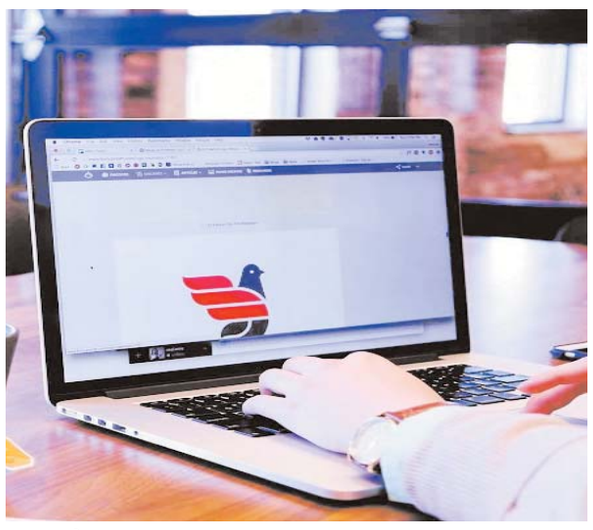

लैपटॉप पर काम करते हुए अपनी दिशा का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सही दिशा में बैठकर लैपटॉप पर काम करने से आपके काम सकारात्मक असर पड़ता है। वास्तु के मुताबिक लैपटॉप पर काम करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए।

आज के इस दौर में अधिकतर लोग अपना काम घर पर ही बैठकर करते है। लैपटॉप से ही उनके दिन भर के सारे काम होते हैं। ऐसे में दिनभर के कामों से उनके दिमाग में तनाव आ जाता है और मन की निगेटिविटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए, लैपटॉप पर काम करते हुए अपनी दिशा का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सही दिशा में बैठकर लैपटॉप पर काम करने से आपके काम पर ही नहीं बल्कि आसपास के माहौल पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।

हांलाकि अधिकतर लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं जबकि यह उनके लिए अधिक जरूरी होता है। ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने जा रहे हैं कि लैपटॉप पर काम करने के दौरान किस दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए।

इस दिशा में रखें मुख

लैपटॉप पर काम करने के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर मुख करके लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। वास्तु के मुताबिक लैपटॉप पर काम करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। जिससे आपके काम करने की जगह पर सकारात्मकता आती है।

पूर्व दिशा की ओर मुख होने पर

लैपटॉप पर काम करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, तो प्रयास करें आपका लैपटॉप थोड़ा सा दांई तरफ हो। ऐसा करने से लैपटॉप पूर्व दक्षिण दिशा में होगा, यह दिशा काम के लिए एकदम सही है। वहीं उत्तर दिशा की ओर मुख करके लैपटॉप पर काम करते हैं, तो ध्यान रखें कि लैपटॉप थोड़ा सा बांई ओर होनी चाहिए। टेबल को थोड़ा सा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए।

लैपटॉप पर काम करते समय दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप काम के बीच में एक-दो घंटे का ब्रेक ले रहे हैं तो उस दौरान लैपटॉप को बंद कर देना चाहिए। अधिकतर कुछ लोग अपने लैपटॉप को ऑन ही छोड़ देते हैं। ऐसे करना नकारात्मक माना जाता है, और व्यक्ति सदैव तनाव में रहता है। लैपटॉप से निकल रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्यक्ति के दिमाग व सिर पर गलत असर डालता है। इसीलिए आप भी लैपटॉप पर काम करते समय इन बातों का ध्यान रखें और साथ ही दिशाओं का भी ध्यान रखें जिसको करने से आपके काम पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

पितरों के नाराज होने पर मिलने लगते हैं ऐसे संकेत, ऐसे करेंगे पूजा को मिलेगा दोष से छुटकारा

पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख-शान्ति बनी रहती है। लेकिन पूर्वजों के नाराज होने पर कई पीढ़ियों तक पितृ दोष का कष्ट झेलना पड़ता है। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिससे आपके घर में खुशियां आ सकती हैं।

पितृ दोष होने पर मिलते हैं ऐसे संकेत

अगर आपकी कुण्डली में पितृ दोष है, तो आपको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर बनने वाले काम भी बिगड़ जाते हैं और बिजनेस या नौकरी में रूकावटें आने लगती हैं।

दांपत्य जीवन में आती हैं ऐसी समस्याएं

घर में पितृ दोष होने पर दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिलता है। या फिर दंपत्ति की पैदा हुई संतान मंदबुद्धि, विकलांग आदि होती है। कई बार तो पैदा हुई संतान की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। इससे पता चलता है कि घर में पितृ दोष लगा हुआ है।

इन परेशानियों का करना पड़ता है सामना

पितृ दोष लगने पर घर में किसी न किसी कारण से लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। घर में रह रहे लोगों में कोई न कोई बीमार बना रहता है। दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। इन बातों से पता चलता है कि घर में पितृ दोष लगा है।

जानिए पितृ दोष से बचने के उपाय

यदि कुडंली में पितृ दोष हो, तो पितरों की फोटो को दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए और उनपर माला चढ़ाकर स्मरण करना चाहिए। दोपहर के समय पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही फूल, अक्षत, दूध, गंगाजल के साथ काले तिल चढ़ाकर पितरों का स्मरण करना चाहिए। प्रतिदिन शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। अगर आप रोज दीपक नहीं जला सकते, तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना जलाएं। गरीब कन्याओं का विवाह कराने से और किसी के विवाह में मदद करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।

[भविष्यफल]

मेष
आज का दिन आपके लिए स्पेशल रहेगा। दांपत्य रिश्ते की समस्याएं आज खत्म होगी, एक-दूसरे के साथ रिश्ते की नयी शुरुआत करेंगे।

वृष
आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। दोस्त की खुशी में आज आप शामिल होंगे, उन्हें काफी खुशी होगी।

मिथुन
आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके निजी जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन्हें आप बखूबी पूरा करेंगे। आपका किसी मीटिंग में परफॉर्मेंस अच्छा

कर्क
आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। ऑफिस के रुके कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। आज शांत मन से कोई भी निर्णय लेना बेहतर रहेगा।

सिंह
आज आपका दिन मिला-जुला रहने वाला है। दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहे। जरुरत पड़ने पर आपको मदद लेनी पड़ सकती है।

कन्या
आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज अपने आर्थिक पक्ष को देखते हुए खर्च करेंगे। धन आगमन होने से आप आर्थिक रूप से राहत महसूस

तुला
आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपकी इनकम के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं आज समाप्त होंगी।

वृश्चिक
आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज हैवी ट्रैफिक की वजह से आपको ऑफिस के लिए लेट हो सकता है।

धनु
आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। बड़े भाई की सहायता से काम को जल्द और आसानी से पूरा कर लेंगे।

मकर
आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आप पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इस राशि के राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यों में रूचि लेंगे।

कुंभ
आज आपका दिन खुशियां भरा रहने वाला है। सिंगर्स को किसी एल्बम की प्रसिद्धि के लिए सम्मानित किया जायेगा।

मीन
आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज कुछ नया करने का विचार करेंगे। बॉस आपके काम की तारीफ़ करेंगे।

रुके हुए और बिगड़े हुए काम बना देते हैं भगवान सूर्य नारायण

शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान सूर्य की स्तुति करता है, रविवार को व्रत रखता है और सुबह-सुबह उन्हें अर्घ्य देता है उसके जीवन में सुख और शांति तो आती ही है साथ ही उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूरी होती हैं। शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देव बताया गया है जिनके दर्शन हर कोई कर सकता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल लेकर और उसमें लाल फूल, चावल डालकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर भक्त को दीर्घायु, आरोग्य, धन, धान्य, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं। रविवार सूर्य पूजा का दिवस होता है इसलिए यदि इस दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की जाये और उनकी कथा सुनी जाए तो असीम लाभ प्राप्त होता है।

सूर्य पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए-

- सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर स्नान कर लेना चाहिए।
- भगवान श्री सूर्य नारायण को तीन बार अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए।
- संध्या के समय भी श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर प्रणाम करें।
- आदित्य हृदय का नियमित पाठ करने से भगवान श्री सूर्य की कृपा जल्द होती है।
- रविवार को तेल और नमक खाने से बचें और यदि संभव हो तो एक समय ही भोजन करें।
- अर्घ्य हमेशा पूर्व दिशा में देना चाहिए और साफ उच्चारण के साथ सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए।
- अर्घ्य देने के बाद हो उस जल को अपने माथे पर लगाना अच्छा माना जाता है।
- ध्यान दें कि जब अर्घ्य देने जा रहे हैं तो जल का बर्तन तांबे का होना चाहिए।

सूर्य पूजा के लाभ इस प्रकार हैं-

- श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
- रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं और सफलता मिलती है।
- जीवन में आ रही बाधाएं अचानक दूर होने लगती हैं।
- घर परिवार में सुख और शांति का वास होता है।
- वैभव, यश, भाग्य और विद्या में वृद्धि होती है।

इस प्रकार आप सभी भगवान श्री सूर्य नारायण की सच्चे मन से आराधना कर अपना जीवन सुधार सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जरूरी नहीं कि आप मंदिर में बैठ कर ही सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र को अपने मोबाइल या कम्प्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं और जब भी समय मिले सच्चे मन से ध्यान लगाएं और अपनी मनोकामना प्रभु को बताएं, निश्चित ही आपका कल्याण होगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

जातीय जनगणना सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

नई दिल्ली। बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसके साथ ही एससी ने कहा कि आंकड़ें प्रकाशित होने से हम नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकार के नीति निर्माण में दखलअंदाजी नहीं कर सकते हैं। याचिका पर सुनवाई संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने की है। यह सुनवाई पटना हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती वाली याचिका पर अपना आदेश रखा है। बताते चले कि पटना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बिहार सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए हरी झंडी दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने बिहार सरकार से अगले चार हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील की मानें तो बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नहीं है और सर्वे के लिए जानकारी इकट्ठा करने का कोई वैध उद्देश्य नहीं था।

शराब घोटाला पूरी तरह झूठ है केंद्र के पास कोई सबूत नहीं

नईदिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है। उनके पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है, सब बेबुनियाद है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने हमारी इतनी जांच की, क्या कुछ निकला?... आपने कल सुप्रीम कोर्ट में सुना, पूरा शराब घोटाला झूठा है, एक पैसे का भी लेन-देन नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि जज सबूत मांगते रहे लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। कुछ दिनों में शराब घोटाला बंद हो जाएगा और वे कुछ और लेकर आएंगे। वे बस इतना चाहते हैं कि लोगों को एजेंसियों और जांचों में उलझाए रखा जाए। वे न तो खुद काम करेंगे और न ही किसी को काम करने देंगे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी नेताओं में डर पैदा करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले गढ़े जा रहे हैं।

आप में भ्रष्टाचार आम बात हो गई : सुधांशु त्रिवेदी

नई दिल्ली। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि अब आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व डिप्टी सीएम भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। दोनों को अभी तक कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। सुधांश के अनुसार, न्यायालय ने कहा है कि जिस प्रकार के सुबूत संजय सिंह के विरुद्ध पैसे के लेन-देन को लेकर कोर्ट को प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हिरासत में रखकर पूछताछ होना बेहद जरुरी है। भाजपा नेता ने कहा कि संजय सिंह राज्यसभा सांसद है कोई आम बात नहीं है। उन्होंने आगे टिप्पणी कर कहा कि इस कारण आम आदमी पार्टी का किरदार देश के सामने तारतार हो गया है। राज्यसभा के अनुसार आम आदमी पार्टी जिन मूल्यों को स्थापित करने का दावा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अपने कामों से वो एक मूल्यहीन पार्टी बनकर रह गई है।

बंगाल बाढ़ पर अधीर रंजन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

कोलकाता। पश्चिम बंगाल और सिक्किम एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों को पत्र लिखकर उनसे दोष न देने और लोगों की मदद करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति पर जोर दिया, खासकर पूर्व और पश्चिम बर्दवान, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम सहित सात जिलों में। उन्होंने लिखा कि यह समय एक-दूसरे पर दोष मढ़ने का नहीं, बल्कि बाढ़ के कारणों पर निर्णय लेने का है। चौधरी ने पीएम मोदी को लिखा कि आइए हम बाढ़ के मानव निर्मित या ईश्वर निर्मित कारणों पर विवाद को एक तरफ रख दें। अब समय आ गया है कि प्रभावित लोगों को बचाया जाए, अपने मतभेदों को भुलाकर उन्हें भोजन, पीने का पानी और दवाएँ दी जाएँ।

ईडी की पूछताछ से बचने सोरेन ने ली हाईकोर्ट की शरण

रांची। ईडी के द्वारा पूछताछ से बचने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट अब 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आज आंशिक रूप से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस याचिका में कुछ त्रुटियां है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस याचिका में जो त्रुटियां हैं, उसे दूर करने का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। प्रार्थी हेमंत सोरेन द्वारा याचिका में ईडी के समन एवं उसके अधिकार को चुनौती दी गई है। याचिका में पीएमएलए एक्ट -2002 की धारा-50 व 63 की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करती हैं।

परिवारवादी पार्टियों के बीच भाजपा ही राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी: नड्डा

तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष ने बीआरएस को बताया भ्रष्टाचार रिश्वत समिति, कांग्रेस पर भी निशाना साधा

हैदराबाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में भाजपा राज्य परिषद की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तेलंगाना में इस साल विधानसभा के चुनाव होने है और भाजपा वहां अपनी ताकत लगा रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग चुनाव से पूर्व अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ताकि चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हो। इसलिए आप नीतियों और मुद्दों से लैस होकर और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव में भाग लेते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। यह जरूरी है कि हम स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर प्रदान करें जो हमारे सच्चे इरादों को दर्शाते हों। भाजपा का प्रत्येक सदस्य गर्व से कह सकता है कि भाजपा इन तीनों आयामों के लिए समाधान प्रदान करती है।

जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं....अति गरीबी 1% से भी कम हो गई, ये आईएमएफ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, ये सभी पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं... बीआरएस भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है। यह एक पारिवारिक पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि सोनिया-राहुल-प्रियंका की पार्टी है, एकमात्र राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल के रूप में लड़ रहा है वह भाजपा है। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि हमें ध्यान रखना है कि हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जिसके बारे में कोई भी विषय अकाट्य है। आप चुनाव में जाएंगे तो प्रदेश के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे आपके सामने आएंगे। लेकिन हमें अपने उत्तर के बारे में स्पष्ट होना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज, हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व वाली भाजपा सक्रिय रूप से समाज के हर वर्ग को सशक्त बना रही है। गरीबी हटाने के नाम पर इंदिरा गांधी ने गरीबों को हटा दिया। वहीं, पीएम मोदी को 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आज देश में रोड, हाइवे, एयर वे और वाटर वे सभी पर कार्य चल रहा है। आज अगर दुनिया भारत की सराहना कर रही है तो इसका कारण देश में महिलाओं, किसानों और युवाओं का सशक्तिकरण है।

नड्डा ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे अपनी स्थापना के बाद से ही सुसंगत रहने का गौरव प्राप्त है, जबकि अन्य लोग समय के आधार पर अपने दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। भाजपा अपनी बात पर चलने में गर्व महसूस करती है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया, जिससे उनकी उपेक्षा के कारण राज्यों में क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। अब ये क्षेत्रीय पार्टियाँ धीरे-धीरे परिवार संचालित पार्टियों में तब्दील होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एकमात्र राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल के रूप में लड़ रहा है वह भारतीय जनता पार्टी है। परिवार-केंद्रित पार्टियाँ कभी भी राष्ट्र को पहले स्थान पर नहीं रखेंगी। भारत का लोकतंत्र किसी परिवार विशेष का अधीन नहीं होना चाहिए!

दो वर्ष में देश से पूरी तरह खत्म हो जाएगा वामपंथी उग्रवाद : शाह

नईदिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जहां 2010 की तुलना में 2022 में हिंसक घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी शामिल हुए, वहीं ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राज्य के मंत्रियों ने किया। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इसे इसके सभी रूपों में उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि दो वर्ष में देश से वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में देश में वामपंथी उग्रवाद सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने 2015 में %एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना% को मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने कहा कि नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति के दृढ़ कार्यान्वयन से देश भर में वामपंथी हिंसा में लगातार गिरावट आई है। परिकल्पना में सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास संबंधी कामकाज, स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारी सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति के लगातार कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश भर में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगातार कमी आई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 2010 के उच्च स्तर के मुकाबले 2022 में 77 प्रतिशत की कमी आई है।

जदयू सांसद ने जातीय जनगणना पर नीतीश को ही कटघरे में खड़ा किया

सुनील कुमार पिंटू जहां से आए थे, जाने का मन बना लिया : संजय झा

पटना। बिहार में सत्ताधारी दल जदयू में जारी आंतरिक कलह धिरे-धिरे जोर पकड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा वैसे-वैसे जदयू में भारी असंतोष पनपते जा रहा है। जदयू के अंदर भगदड़ मचने की स्थिति है। नीतीश कुमार के एक सांसद सुनील कुमार पिंटू ने तो जातीय गणना कि रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।

सीतामढ़ी से जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री के खास मंत्री संजय झा ने साफ-साफ कह दिया कि वे जहां से आए थे, वहीं जाने का मन बना लिया होगा। इससे स्पष्ट है कि कि जदयू ने मान लिया है कि उनके सांसद भाजपा में जाने वाले हैं। दरअसल, जातीय गणना पर सांसद सुनील कुमार पिंटू ने गुरुवार को कहा था कि जातीय गणना में फर्जीवाड़ा किया गया है। इसमें तेली समाज की संख्या को कम कर दिया गया है। तेली समाज की कई बस्तियों, मोहल्लों में गणना करने वाले पहुंचे ही नहीं। सुनील पिंटू ने रविवार को पटना में तेली समाज की बैठक भी बुलाई है। आज मंत्री संजय झा से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुनील कुमार पिंटू जहां से आये हैं, वहीं वापस जाना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं।

नीतीश कुमार ने जातीय गणना करा कर ऐतिहासिक काम किया है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बता दें कि जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान ही भाजपा से जदयू में शामिल हुए थे। इसके बाद जदयू ने उन्हें सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाया था। वे भाजपा के टिकट पर सीतामढ़ी से विधायक भी रहे हैं और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा-जदयू में आपसी समझौता के तहत सुनील कुमार पिंटू जदयू में शामिल हुए टिकट लिए और जीत भी हुई। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि सीटिंग सांसद क्या दल छोड़ने वाले हैं? क्या वे भाजपा में जाएंगे? ऐसे में क्या जदयू अपनी सीटिंग सीट सीतामढ़ी सहयोगी दल राजद को सौंप देगी या फिर अपना उम्मीदवार देगी ? जदयू अगर सीतामढ़ी सीट नहीं छोड़ेगी तो फिर उम्मीदवार कौन होंगे? क्या विधानपरिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जदयू के प्रत्याशी होंगे? विधान परिषद सभापति देवेशचंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से ही आते हैं। जानकार बताते हैं कि वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। सिर्फ पार्टी नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं।

जाति सर्वेक्षण के लिए लगे कर्मचारियों को भुगतान के लिए दिए गए 212 करोड़

बिहार सरकार ने गुरुवार को जाति सर्वेक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान के लिए 212.77 करोड़ रुपये की राशि जारी की। मामले से वाकिफ अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यह धनराशि सभी जिलों को रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से जारी की गई। पटना को सबसे अधिक 11.49 करोड़ रुपये मिले हैं, इसके बाद मुजफ्फरपुर (10.16 करोड़ रुपये), मोतिहारी (9.57 करोड़ रुपये) और गया (9.30 करोड़ रुपये) हैं। सबसे छोटे जिले अरवल को 1.59 करोड़ रुपये मिले हैं। सरकार ने राशि जारी करते हुए कहा कि प्रावधानों के अनुरूप भुगतान किया जाये।

खेल
प्रमुख समाचार

बांग्लादेश को हराकर भारत पुरुष क्रिकेट के फाइनल में

हांगझोऊ। खिताब के प्रबल दावेदार भारत ने शुक्रवार को यहां सेमीफाइनल में बांग्लादेश को नौ विकेट से रौंदकर पुरुष क्रिकेट के फाइनल में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित किया। भारतीय कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और गेंदबाजों ने इसे सही साबित करते हुए बांग्लादेश को 20 ओवर में नौ विकेट पर 96 रन के स्कोर पर रोक दिया। भारत ने इसके जवाब में 9.2 ओवर में एक विकेट पर 97 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

भारतीय टीम पहली बार महाद्वीपीय खेलों की इस स्पर्धा में हिस्सा ले रही है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पहले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवा दिया जो खाता भी नहीं खोल पाए। कप्तान और सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ (26 गेंद में नाबाद 40, चार चौके, तीन छक्के) और तिलक वर्मा (26 गेंद में नाबाद 55, दो चौके, छह छक्के) ने इसके बाद 97 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को आसान जीत दिला दी। उभरते हुए ऑलराउंडर वर्मा ने सिर्फ 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और फिर भावनात्मक जश्न मनाते हुए अपनी शर्ट उठाकर अपने माता-पिता को समर्पित टैटू दिखाया। भारत स्वर्ण पदक के मुकाबले में शनिवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगा। इससे पहले साई किशोर भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 12 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वाशिंगटन सुंदर ने भी 15 रन देकर दो विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई और शाहबाज अहमद को भी एक-एक विकेट मिला। गायकवाड़ और वर्मा ने छोटे मैदान पर अधिकांश रन बाउंड्री से बटोरे। बांग्लदेश के गेंदबाजों के पास गायकवाड़ और वर्मा का कोई जवाब नहीं था जिन्होंने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 364 अंक चढ़ा निफ्टी भी 19,650 के पार

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले मिश्रित रूझानों के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 364 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 106 अंकों की बढ़त देखी गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.66 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक 0.56 प्रतिशत बढ़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 364.06 अंक यानी 0.55 फीसदी की बढ़त के साथ 65,995.63 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,095.81 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,762.33 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी में भी 105.70 अंक यानी 0.54 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,651.45 अंक पर बंद हुआ।

रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर बरकरार

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई ने यथास्थिति बरकरार रखी और रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा। यह चौथी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। दास ने कहा, उभरते व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और दृष्टिकोण के विस्तृत मूल्यांकन के बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीति रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। दास की घोषणा आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 4 से 6 अक्टूबर तक हुई बैठक के बाद आई।

रिजर्व बैंक ने 2 साल के लिए बढ़ाई पीआईडीएफ स्कीम

मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी के नतीजों का ऐलान करते हुए 6 अक्टूबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) का विस्तार जारी है। इसी क्रम में पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड स्कीम को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम की अवधि को दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ, अब पीआईडीएफ स्कीम में पीएम विश्वकर्मा योजना को भी शामिल किया गया है। बता दें, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 250 करोड़ रुपये के शुरुआती योगदान के साथ शुरू किया गया था। आरबीआई का यह इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पूरी तरह से पीओएस सिस्टम के लिए है। पीओएस मशीन पेमेंट लेने का एक जरिया है। आप अक्सर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय इस मशीन का इस्तेमाल देखते होंगे। व्यापारी इसी मशीन से डिजिटल पेमेंट प्राप्त करते हैं।

डब्ल्यूटीओ ने ट्रेड ग्रोथ का अनुमान घटाकर 0.8% किया

नईदिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 2023 के लिये व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर 0.8 प्रतिशत कर दिया है। वैश्विक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में नरमी के बीच यह अनुमान घटाया गया है। डब्ल्यूटीओ ने बयान में कहा कि 2022 की चौथी तिमाही में शुरू हुई नरमी के बीच विश्व व्यापार संगठन के अर्थशास्त्रियों ने 2023 के लिये वैश्विक स्तर पर वस्तु व्यापार में वृद्धि के अनुमान को घटाया है। बयान के अनुसार, ''दुनिया में वस्तु व्यापार की मात्रा इस वर्ष 0.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह अप्रैल में जताये गये 1.7 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान का आधे से भी कम है।'' हालांकि, डब्ल्यूटीओ ने 2024 के लिये 3.3 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान को बरकरार रखा है। बयान में कहा गया है कि वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में विश्व व्यापार और उत्पादन में अचानक से नरमी आई।

अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी की चुनौती

सरोज कुमार

कृषि अर्थव्यवस्था का इकलौता क्षेत्र है, जो घाटे के बावजूद बंद नहीं होता। यहां श्रमशक्ति का लगभग 45-50 फीसद हिस्सा रोजगार पाता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार मौसमी होते हैं। फिर भी इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए तो भारत की बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है।

कोई अवस्था लंबी अवधि तक बनी रहे तो उसके प्रति सहज भावना पैदा होने लगती है। यह सहजता धीरे-धीरे स्थायी हो जाती है। एक सीमा के बाद दर्द का अहसास न होना इसी प्रक्रिया का परिणाम है। बेरोजगारी के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्थायी भाव अच्छा संकेत नहीं है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक औसत बेरोजगारी दर 7.6 फीसद के उच्चस्तर पर बनी रही। लेकिन कहीं से कोई खास विमर्श का स्वर सुनाई नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि शायद बेरोजगारी का अहसास जाता रहा! यह मानव मन में बेरोजगारी के सहज हो जाने का संकेत है। बेरोजगारी का स्थायी भाव अस्थिरता है। यानी बेरोजगारी जितनी स्थायी होगी, अस्थिरता उतनी ही बढ़ती जाएगी।

अस्थिरता क्या कुछ करती है, बताने की जरूरत नहीं। मनोभावों के बदलने से आंकड़े नहीं बदलते। अलबत्ता आंकड़े मनोभावों को बदल देते हैं। बेरोजगारी का सवाल आंकड़ों से आगे का है और मानव मन आज इसी सवाल में उलझ कर रह गया है। बेरोजगारी के आंकड़े इतने भारी हो गए हैं कि अब इन्हें न तो मानव मन ढो पाने की स्थिति में है, और न अर्थव्यवस्था ही। 'सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी' (सीएमआईई) के

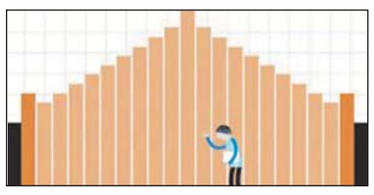

अनुसार, बीते वित्त वर्ष में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक की औसत मासिक वृद्धि दर 2.68 फीसद रही।

इस धीमी वृद्धि दर का परिणाम है कि उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक महामारी से पूर्व के स्तर पर आज तक नहीं पहुंच पाया। मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भी उस स्तर पर पहुंचने की संभावना कम है। महामारी से ठीक पहले फरवरी 2020 में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक 105.3 पर था, जो मार्च 2023 में 89.18 पर दर्ज किया गया। मानसून पर संभावित अल नीनो प्रभाव और निजी निवेश में अनवरत सुस्ती के मद्देनजर मौजूदा वित्त वर्ष में भी उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक का संभवत: यही हाल रहने वाला है। उपभोक्ता मनोभाव का ऊपर उठना आमदनी पर निर्भर करता है और ऊंची बेरोजगारी दर इसकी संभावना को धूमिल कर देती है। जाहिर है, इसका असर अर्थव्यवस्था पर होगा और अर्थव्यवस्था का असर मानव जीवन पर, सामाजिक ताने-बाने पर। बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4.4 फीसद रह गई और चौथी तिमाही में इसके और नीचे जाने की आशंका है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच मौजूदा वित्त वर्ष का परिदृश्य भी सुखद नहीं है। वैश्विक वित्तीय एजंसियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान घटा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने 6.1 फीसद के अपने अनुमान को घटाकर 5.90 फीसद कर दिया। विश्व बैंक ने 6.6 फीसद के अनुमान को घटाकर 6.3 फीसद और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने अपने अनुमान को 7.2 फीसद से घटाकर 6.4 फीसद कर दिया है। नोमुरा के अनुसार, भारत की वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में 5.3 फीसद रहनी है। बेशक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मौजूदा वित्त वर्ष की अपनी पहली नीतिगत समीक्षा में विकास दर अनुमान को 6.4 फीसद से बढ़ाकर 6.5 फीसद किया, लेकिन विशेषज्ञों की नजर में यह अति आशावादी आंकड़ा है। बेरोजगारी दर के आंकड़े दो प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं- श्रमिक भागीदारी दर और रोजगार सृजन। श्रम बाजार में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ गई और उसके अनुसार रोजगार सृजन नहीं हुआ तो बेरोजगारी दर ऊंची दिखेगी। रोजगार सृजन नहीं भी हुआ, मगर श्रमिक भागीदारी घट गई तो बेरोजगारी दर नीचे दिखेगी। लेकिन यहां तो श्रमिक भागीदारी घटने के बाद भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है।

कौन कहता है कि वक्त सारे ज़ख्म भर देता है...

भाजपा के आलाकमान (मोदी-शाह) ने 'मिशन 2024' के लिए अभी से अपनी कमर कस ली है।पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों से पार्टी का आडवाणीकरण करने पर विचार कर रहे हैं.....इस रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। पार्टी के तमाम बुजुर्ग नेता अब अपनी भूमिका को लेकर चिंता में हैं..?बुजुर्ग नेताओं को दो बड़ी चिंताएं सता रही हैं एक

तो यह कि टिकट पाने के लिए जो शर्त है, उस पर खरे उतरेंगे या नहीं.... दूसरी अगर टिकट मिला और चुनाव जीत भी गए, तो उन्हें 'अहमियत' भी मिलेगी या नहीं.... यदि वो मंत्री ना बने तो उनके राजनीति में होने-न-होने का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा।जानकारी के मुताबिक पहले 2024 में बीजेपी 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को टिकट नहीं देने की चर्चा थी,पर अब तो 60+के सांसद निशाने पर हैं?पीएम नरेन्द्र मोदी का 73वां जन्मदिन हाल ही में मनाया....पर 2024 में तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है...तो उन पर यह लागू नहीं होगा...? 70+वाला यदि नियम लागू हुआ तो 81 सांसदों के टिकट कट जाएंगे। बुजुर्ग सांसदों में सबसे ज्यादा उप्र से 12, गुजरात से 10, कर्नाटक से 9, महाराष्ट्र से 5, झारखंड से 2, बिहार से 6,मध्य प्रदेश से 5 और राजस्थान से 5 हैं।इधर पार्टी का मानना है कि इस फैसले से नए लोगों को राजनीति में आगे आने का मौका मिलेगा।पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से तमाम ऐसे नेताओं को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया,जो अटल सरकार में भी मंत्री रहे थे,इन नेताओं में बिहार से पार्टी के सबसे बड़े नेता समझे जाने वाले रविशंकर प्रसाद,उत्तराखंड के दिग्गज नेता रमेश पोखरियाल निशंक,महाराष्ट्र के बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी में मुस्लिम बड़े चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं।ये वो नेता हैं जिनके लिए कहा जाता था कि इनके बिना भाजपा की केंद्रीय राजनीति चल ही नहीं सकती।मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं।मोदी सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे राजनाथ सिंह की बढ़ती उम्र राजनीतिक भविष्य के लिए संकट बन चुकी है. 71 वर्षीय राजनाथ सिंह उप्र में भाजपा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, पीएम मोदी उन्हें अपनी कैबिनेट से बाहर करके उप्र की जनता को नाराज नहीं करना चाहते हैं।हालांकि अब उप्र में राजनाथ से बड़े नेता सीएम योगी स्थापित हो चुके हैं। राजनाथ 72 का आंकड़ा पार कर चुके हैं,लिहाजा 2024 में वे मार्गदर्शक मंडल में ही नजर आएंगे,नितिन गडकरी वैसे तो मोदी सरकार में सबसे कर्मठ मंत्री माने जाते हैं,लेकिन 2024 में उनकी उम्र भी 70+ हो जाएगी, इसलिये उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में डाला जा सकता है....?गडकरी को भी इसका आभास होने लगा है।उप्र में भाजपा के वयोवृद्ध नेता डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय सिर्फ ब्राह्मण चेहरा होने के कारण मोदी सरकार में जगह बना पाए थे।उनकी सेहत और उम्र दोनों अब उनका साथ नहीं दे रही है हो सकता है कि 2024 में वे खुद से ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दें।हरदीप सिंह पुरी वर्तमान समय में मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं, भाजपा में कोई सिख नेता नहीं होने के कारण उन्हें तरजीह दी गई है।वे भी 2024 में सन्यास ले सकते हैं,यदि ऐसा नहीं होगा तो उनकी सेहत को देखते हुए टिकट मिल पाना बड़ा असंभव नजर आ रहा है।मोदी सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहीं निर्मला सीतारमण भीआर्थिक मोर्चों पर अक्सर फेल साबित होते नजर आती हैं. मौजूदा समय में भी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही हैं।इसलिये 2024 में वे भी मार्गदर्शक मंडल में दिखाई दे सकती है....?इधर हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नरेन्द्र तोमर (66साल)प्रहलाद पटेल (63साल)फग्गन सिँह कुलस्ते (64साल) ए के विजयवर्गीय (67साल)सहित 7लोस सदस्यों को विधानसभा का टिकट दिया है वहीं एक अन्य मंत्री ज्योतिरदित्य सिंधिया को भी विस चुनाव लड़ाने की चर्चा है तो छ्ग से सांसद विजय बघेल (64साल)को सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ विस प्रत्याशी बनाया है तो कुछ अन्य सांसदों को भी विस चुनाव लड़ाने की चर्चा तेज है। वैसे यदि विस चुनाव जीत गये तो विधायकऔर हार गये तो दोनों स्थितियों में लोस टिकट से वंचित हो ही जाएंगे?

मप्र के सीएम शिवराज की पहल अनुकरणीय......

मप्र के सीएम शिवराजसिंह ने हाल ही में एक नई पहल की है और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा होना चाहिये।ताकि आनेवाली पीढ़ी के लिये यह प्रेरणादायक बन सके।मप्र सीएम शिवराज ने भोपाल के वल्लभ भवन में स्थापित की गई 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं ब्रॉन्ज की है। जिन्हें नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 1 करोड़ तीन लाख 56 हजार रुपए की राशि से तैयार किया गया है।प्रतिमाओं के मॉडल तैयार करने के बाद इन्हें दिवंगत मुख्यमंत्रियों के परिजनों को समय-समय पर दिखाया गया,ताकि पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं को हूबहू तैयार किया जा सके।परिजनों की सलाह के बाद 31 मार्च 2023 को इन प्रतिमाओं को तैयार किया गया। जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं,उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, राजा नरेश चंद्र सिंह, श्यामाचरण शुक्ला, प्रकाश चंद्र सेठी,कैलाश चंद्र जोशी, वीरेन्द्र खलेचा,सुंदरलाल पटवा,अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोरा,बाबूलाल गौर शामिल हैं ।

मप्र के 6 सीएम का छत्तीसगढ़िया कनेक्शन...

एक नवम्बर 1956 में मप्र अस्तित्व में आया और 1 नवम्बर 2000 को विभाजित होकर छत्तीसगढ़ का उदय हुआ।अविभाजित मप्र में छत्तीसगढ़ के 6 नेता सीएम बने। द्वारिका प्रसाद मिश्रा की शिक्षा रायपुर में हुई थी और वे कसडोल से विस उप चुनाव जीतकर सीएम की गद्दी बरकरार रखा तो अर्जुनसिँह ने खरसिया विस से उप चुनाव जीतकर सीएम का पद बरकरार रखा,वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल,राजा नरेशचंद्र सिंह,श्यामाचरण शुक्ला,मोतीलाल वोरा की जड़ें तो छ्ग से ही जुड़ीं थीं। सबसे कम समय तक सीएम राजा नरेश चंद्र सिंह रहे तो 3बार सीएम बनने का रिकार्ड पं.श्यामाचरण शुक्ल के नाम दर्ज है।पंडित रविशंकर शुक्ल 1नवम्बर 1956से 31दिसम्बर 56तक सीएम रहे तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा 30 सितम्बर 1963से 8मार्च 67, राजा नरेश चंद्र 13 मार्च 1969से 25मार्च 69,पं. श्यामाचरण शुक्ल (1)26मार्च 1969से 28जनवरी 72,(2)23मार्च 1975से 30 अप्रेल 77, (3)9जनवरी 89से 1मार्च 90,अर्जुनसिंह 14 फरवरी 88से 23जनवरी 89 (खरसिया उप चुनाव में जीत के बाद)मोतीलाल वोरा (1)13 मार्च 1985से 13मार्च 88 (2)25 जनवरी 89से 9 दिसम्बर 89 तक सीएम रहे।

छ्ग के 3 सीएम अजीत जोगी,डॉ रमन और भूपेश बघेल....

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहले सीएम

अजीत जोगी बने। उन्होंने 9नवम्बर2000से6दिसम्बर 2003 तक यह जिम्मेदारी सम्हाली फिर डॉ रमन सिंह लगातार 3 बार सीएम बनकर रिकार्ड बना चुके हैं। डॉ रमन सिँह (1)7दिसम्बर 2003से 12दिसम्बर 2008 (2)12दिसम्बर 2008से12दिसम्बर 2013(3)12 दिसम्बर 2013से 17दिसम्बर 18 तक सीएम रहे तो वर्तमान सीएम भूपेश बघेल ने 17दिसम्बर 2018से अभी तक सीएम का पदभार सम्हाल रहे हैं।

और अब बस....

- छ्ग के वरिष्ठ आईपीएस (रिटायर)गिरधारी नायक को फिर मानव अधिकार की जिम्मेदारी दी गई है।
- छ्ग के कुछ आईएएस, आईपीएस क्यों चाहते हैं कि छ्ग में भाजपा की सरकार बनें....?
- छ्ग में करीब 9 एसएस पी/एसपी ईडी के निशाने पर हैं...?

एबीवीपी का रायपुर में विशाल प्रदर्शन, जुटे हजारों छात्र

रायपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुई धांधली, प्रदेश में महिलाओं के लगातार बढ़ते उत्पीड़न सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हजारों की संख्या में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से विद्यार्थी रायपुर पहुंचे और सरकार की विफलताओं तथा भ्रष्टाचार का विरोध किया। भूपेश बघेल सरकार द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से करा पाने असफलता तथा अक्षमता से गुस्साए प्रदेश के छात्र सीएम आवास के पास पहुंचे और सरकार की विफलताओं पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर लाठी चार्ज की?। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं तथा लोकतांत्रिक प्रदर्शन में छात्रों के साथ राज्य प्रायोजित पुलिसिया दमन का विरोध करती है। अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री

याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिन भी रिक्त पदों पर भर्तियां आती हैं उसमें प्रदेश में पद पर आसीन मंत्रियों द्वारा अपने करीबियों को दिलवा दिया जाता है। पीएससी 2022 परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी के उजागर होने से पीएससी परीक्षा के लिए दिन-रात एक कर देने वाले युवाओं को न केवल निराशा और दु:ख हुआ बल्कि वे आक्रोशित भी हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गड़बड़ी की आशंका को प्रथमदृष्ट्या न नकारना भी गड़बड़ी के संदेह को ही पुष्ट करता है। ऐसे में अभाविप द्वारा किए गए इस आंदोलन में प्रदेश भर से लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए जाने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी व अपनी गिरफ्तारी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार रोज़ नए घोटाले किए जा रही है, प्रदेश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहां जनता की सेवा करने की जगह प्रदेश के नेता खुद के घर की सेवा करने में मस्त हैं, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं उल्टा महिला संबंधी अपराधों में प्रदेश के नेता स्वयं संलिप्तता रही है। प्रदेश में जल्दी भर्तियां नहीं आती हैं और आती है तो मनमाने ढंग से अपने परिवारजनों को रिक्त पदों पर बैठा, आम छात्र का हक़ छीन लिया जाता है। अभाविप की यह रैली सरकार को सख्त हिदायत देने को है कि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करे अन्यथा जनता भूपेश सरकार को उठा फेंकने का काम करेगी। अभाविप छत्तीसगढ़ प्रदेश मंत्री श्री मनोज वैष्णव ने कहा कि सीजीपीएससी की 2021 परीक्षा में पीएससी चेयरमैन समेत कई अधिकारियों और नेताओं के बेहद करीबी रिश्तेदारों की भर्ती के बाद अब 2022 पीएससी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी के उजागर होने से पीएससी परीक्षा के लिए दिन-रात एक कर देने वाले युवाओं को न केवल निराशा और दु:ख हुआ बल्कि वे आक्रोशित भी हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गड़बड़ी की आशंका को प्रथमदृष्ट्या न नकारना भी गड़बड़ी के संदेह को ही पुष्ट करता है।

पट्टा वितरण में भेदभाव व अनियमितता के विरोध में भाजपा का जंगी प्रदर्शन

रायपुर। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार द्वारा पट्टा वितरण के तरीके से गरीबों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। लोग सड़क पर उतर गए है। गरीब बस्तियों में खलबली मच गई है। अभी दो चार दिनों में आचार संहिता लगने वाला है और अब जाकर प्रदेश सरकार द्वारा पट्टा वितरण किया जा रहा है परंतु शासन द्वारा पट्टा वितरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उससे गरीब में भी भेदभावपूर्ण रैवैया अपनाया गया है जिससे जनाक्रोश बढता जा रहा है। जनाक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तात्यापारा मंडल क्षेत्र के नेताओं द्वारा आज गरीबों बस्तियों के नागरिकों के साथ मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर के

नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नगर निगम के ज़ोन सात कमिशनरी में जमकर हल्ला बोला और अव्यवहारिक पट्टा वितरण के तौर तरीकों पर जमकर नाराजगी व्यक्त की गई।रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने प्रदर्शन करने आये नागरिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पट्टा वितरण की जो नीति अपनाई है उससे नागरिकों में गरीबों में खुशी की जगह आक्रोश ज्यादा दिखाई दे रहा है। पूरी की पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित और आनन फानन में चुनावी षडयंत्र के तहत अपनायी गयी प्रक्रिया मात्र है। कांग्रेस सरकार कहीं से भी गरीबों को उपकृत करने का नही अपितु भ्रमित करने का काम कर रही है जिससे गरीबों में भारी जाक्रोश है और इसका परिणाम कॉंग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आगामी चुनाव में भगतना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

पीएससी के नतीजों पर सवाल स्तरहीन राजनीति : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि मुद्दाविहीन भारतीय जनता पार्टी राज्य लोकसेवा आयोग की चयनित सूची पर सवाल खड़ा कर रहा है। दुर्भाग्य से भाजपा अपनी निम्नस्तरीय राजनीति के लिये इन बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रही हम इसकी कड़ी निंदा भी करते है। भारतीय जनता पार्टी बेहद ही गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा रहे कि पीएससी में,

नेताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों के बच्चों के कुछ नाम चयनित हो गये है। रमन सिंह और भाजपा को आपत्ति है कि पीएससी में सगे भाई-बहन, पति-पत्नी का चयन कैसे हो गया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के पीएससी के नतीजों पर सवाल खड़ा करने का कोई भी तार्किक आधार नहीं है क्यों और कैसे पर सवाल खड़ा करके भाजपा प्रदेश के युवाओं के सपनों को पंख लगाने वाली संस्था राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना कर युवाओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे है। भाजपा को आपत्ति है कि कैसे सगे भाई-बहन, पति-पत्नी, अधिकारियों के बच्चे चयनित हो गये? जबकि पीएससी के हर साल की चयन सूची में पराया रिश्तेदार, अधिकारियों के रिश्तेदार, नेताओं के भी रिश्तेदारों के चयन होते है। कांग्रेस ने 15 सालों में भाजपा शासन काल की सूची भी जारी किया था।

छत्तीसगढ़ में महिलाये देश में सबसे ज्यादा सुरक्षितः कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद महिलाओं के जीवन जीने के लिये अपराधमुक्त सुरक्षित वातावरण तैयार हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते है कि छत्तीसगढ़ में पिछले साढ़े 4 साल में महिलाओं के प्रति अपराधों में 78 प्रतिशत की कमी आई है। बलात्कार के मामलों में 62 प्रतिशत और सामूहिक बलात्कार के मामलों में 69 प्रतिशत तक की कमी आई है। घरेलू हिंसा में भी कमी

आई है। राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन में भी छत्तीसगढ़ भाजपा के अंतिम तीन वर्ष (16,17,18) जब राज्य में भाजपा की सरकार थी कि अपेक्षा कांग्रेस राज में अपराधों में कमी आई है। पूर्व रमन भाजपा सरकार के दौरान दुष्कर्म के मामले में 2018 में प्रति लाख आबादी में घटित होने वाले अपराध में देश मे छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर, वर्ष 2017 में दूसरे स्थान पर था। कांग्रेस सरकार के द्वारा मजबूत की गई कानून व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा के लिये उठाएंगे प्रभावी कदम के बाद वर्ष 2023 में इस अपराध में प्रभावी नियंत्रण हुआ आज छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। महिला के विरूद्ध घटित अपराध में छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर 18वें स्थान पर है। अपहरण के अपराध घटित हुये है।राष्ट्रीय स्तर पर इस अपराध में छत्तीसगढ़ 13वें स्थान पर है। असम, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान प्रति लाख आबादी में होने वाले अपहरण के अपराध छत्तीसगढ़ से अधिक है।

भू-एप भाजपा के अपने भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्तिः कांग्रेस

रायपुर। भाजपा के भू-एप्प का जवाब देते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के खून में भ्रष्टाचार है। 15 सालों तक प्रदेश को लूटने वाले भाजपाइयों को सोते जागते भ्रष्टाचार ही दिखता है। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जिस भाजपा के राज्य में रमन सिंह के पुत्र भ्रष्टाचार का पैसा रखने के लिये विदेश में वर्जिन आइलैंड में खाता खोलवाता था, पनामा पेपर में नाम आता

था। जिस भाजपा के राज में मंत्री डॉलर में घूस मांगते थे वह भाजपा किस नैतिकता से एक ईमानदार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। कांग्रेस सरकार की शत-प्रतिशत योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में जाती है यहां भ्रष्टाचार की बातें भाजपा का दिमाकी फितूर है। रमन सरकार के 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पर भाजपा की बोलती क्यों बंद है? 36000 करोड़ का नान घोटाला, 4400 करोड़ के शराब घोटाला, 6000 करोड़ के चिटफंड घोटाले पनामा पेपर वाले अभिषेक सिंह, 1677 करोड़ का गौशाला घोटाले पर, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बृजमोहन अग्रवाल को भी घूस देने की स्वीकारोक्ति प्रमुख आरोपी ने अपने नार्को टेस्ट में किया है। भाजपा के 15 सालों में 34 घोटाले हुये थे जो प्रदेश की जनता के जुबान पर है इनकी जांच कराने की बात आती है तो भाजपाईयों की बोलती बंद हो जाती है।

सीएम बताएं शराब घोटाला क्या अब भी मनगढ़ंत हैः रवि भगत

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अनवर ढ़ेबर की जमानत याचिका रद्द कर दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रवि भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया है की क्या अब भी उन्हें शराब घोटाला मनगढ़ंत है? अगर ऐसा है तो माननीय उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले के तथ्यों और ईडी की कार्यवाही को सही ठहराया है। न्यायालयीन निर्णय के प्रकाश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तत्काल नैतिकता के आधार

पर इस्तीफा देने की मांग करते हुए रवि भगत ने कहा है कि अनवर ढेबर सहित जितने भी लोग शराब घोटाले में शामिल हैं, उन सभी का नार्को टेस्ट कराया जाए। ताकि वह सच उगल सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हुआ शराब घोटाला देश का एक बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में सामने आए तथ्यों पर मुख्यमंत्री को स्वयं संज्ञान लेकर अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत घोटालेबाजों को संरक्षण देते हुए ईडी के तथ्यों को ही गलत ठहरा दिया। छत्तीसगढ़ में घोटाले की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों के बचाव में मुख्यमंत्री स्वयं सामने आते हैं और केंद्रीय एजेंसी पर निराधार आरोप लगाते हुए राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। जबकि उन्हें अपने संवैधानिक पद की मर्यादा के अनुरूप आचरण करते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए।

प्रियंकों क्यों नहीं कहतीं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं : केदार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने सवाल किया है कि प्रियंका गांधी पंच तक नहीं हैं, तब वे किस हैसियत से जनता के पैसे पर पंचइती कर रही हैं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कांकेर में दिए गए भाषण की पंच लाइन टेग लाइन को लेकर लेकर घेरते हुए कहा कि प्रियंका गांधी अक्सर भाजपा शासित राज्यों में जाकर कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के दौरे में कभी भी ऐसा नहीं कहती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हाल ही में कम से कम 4 बार छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में एक बार भी नहीं कहा गया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्योकि वे छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों को पढ़ती होंगी कि पांच साल की लड़की के साथ बलात्कार हो गया, रक्षाबंधन के दिन दो लड़कियों से सामूहिक बलात्कार हो गया, शिक्षक दिवस के दिन ही एक महिला शिक्षक से सामूहिक बलात्कार हुआ, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। एक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। ऐसी अनेक घटनाओं को देखने के बावजूद कभी प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी नहीं किया कि भूपेश जी आप महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा करें। मैंने प्रियंका जी का ट्वीटर एकाउंट देखा है। अगर मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश में छोटी सी भी घटना होती है तो उनका तुरंत ट्वीट आ जाता है।

भूपेश कैबिनेट का फैसला, हड़ताली स्वास्थ्यकर्मियों की बर्खास्तगी की कार्यवाही शून्य

पावर कंपनी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी फैसला किया है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो एक जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए हैं। सरकार के इस फैसले से पावर कंपनी के 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ?इसकी घोषणा शुक्रवार को कांकेर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में की थी। जिस पर कैबिनेट ने इसका त्वरित अनुमोदन किया। रायपुर में सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में

महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड के गठन का फैसला भी हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड के गठन का मकसद

छत्तीसगढ़ में महुआ के वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी और इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। इसके फूल में औषधीय गुण होते हैं और इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है। प्रदेश में महुआ की उपलब्धता, इसके उपयोग और वनक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने से जरूरी था कि इसके विकास के प्रयास किए जाएं। महुआ के फूल, फल और बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके इसीलिए अलग से महुआ बोर्ड बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली

महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने राज्य महुआ बोर्ड का गठन,स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी की कार्यवाही शून्यइससे पहले 26 सितंबर को सीएम भूपेश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। जिसमें एक नवंबर से 20 क्विंटल धान खरीदी, कौशल्या विहार (कमल विहार) में पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15 फीसदी छूट देने का ऐलान किया गया था। साथ ही नवा रायपुर के कमर्शियल हब परियोजना में 540 रुपए वर्ग फीट की दर से व्यापारियों को जमीन देने का ऐलान सीएम भूपेश ने किया था।

शराब घोटाले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर सहित 4 की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला दिया है।याचिका कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी की ओर से लगाई गई थी। चारों आरोपियों को पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार किया था।

ईडी ने सबसे पहले मई के

शुरुआती सप्ताह में अनवर ढेबर को अरेस्ट किया और कहा- साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के काम से पैदा किया। इसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया। ईडी की ओर से कहा गया कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम अपने पॉलिटिकल मास्टर्स (राजनीतिक संरक्षकों) को दी है। इसके बाद इस केस में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह को भी पकड़ गया था। इस केस में फिलहाल अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पर छोड़ा गया है। 22 मई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.